सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

12 फरवरी, 2019

षोडश विधान सभा 12 फरवरी, 2019 ई0

---------------- मंगलवार,तिथि --------------------

द्वादश सत्र 23 माघ, 1040, (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी क्या व्यवस्था है ? किस नियम के विरूद्ध व्यवस्था है ? माननीय सदस्य श्री सत्येदव जी, पहले आप यह सुन लीजिये । व्यवस्था का प्रश्न तब होता है जब सदन की नियमावली के किसी नियम के विरूद्ध कोई कार्य होता रहता है । अभी नियम के विरूद्ध क्या कार्य हुआ है ?

(व्यवधान)

किस नियम का उल्लंघन हुआ है ?

(व्यवधान)

आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री सत्यदेव राम : नियम का उल्लंघन हो रहा है महोदय ।

अध्यक्ष : किस नियम का ?

श्री सत्यदेव राम : न्यूनतम मजदूरी का ।

अध्यक्ष : न्यूनतम मजदूरी विधान सभा की नियमावली में है क्या ? विधान सभा की कार्यवाही विधान सभा के नियम से चलती है । अल्पसूचित प्रश्न-1, श्री अनिल सिंह । माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जवाब दे दिया गया है ।

(इस अवसर पर भा0क0पा0(मा0ले0) एवं सी0पी0आई0 एम0एल0 के माननीय सदस्यगण वेल में आकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग अपनी जगह पर जाईये । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी का भी प्रश्न है । प्रश्नकाल होने दीजिये । अब आप अपनी जगह पर जाकर बैठिये । कहिये न उनको अपने स्थान पर जाने के लिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरा महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : आप इसे कार्य-स्थगन उठाने के समय उठाईयेगा । इनको तो बैठाईये ।

(व्यवधान)

आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जाईये ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर चले गये)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 (श्री अनिल सिंह)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह, जवाब दिया हुआ है ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, रीटेन में जवाब मिला है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि मुफस्सिल निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार के बाहर जिला निबंधन कार्यालय में निबंधन करवाने पर आई0फी लिया जाता है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब वर्ष 2012 के बिहार अधिनियम,11 द्वारा आई0 फी को विलोपित कर दिया गया है तो किस परिस्थिति में फिर आई0 फी लिया जाता है ? यह मेरा पहला पूरक सवाल है ।

दूसरा पूरक यह है कि जब माननीय मंत्री ने वर्ष 2010 में जो रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) विधेयक,2010 लाया, उसके उद्‌देश्य में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जिला के किसी भी निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित/भूमि संपत्ति का निबंधन जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में कराये जाने की सुविधा प्रदान करना ही इस विधेयक का उद्‌देश्य है । महोदय, जब जिला के अंदर कराया जाना है तो सबडिविजन में अलग और जिला में अलग क्यों फीस लिया जा रहा है ? तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब निबंधन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होता है तो यूनिट जिला होना चाहिए, न कि अनुमंडल ।

अध्यक्ष : पहले तो आप आसन के एक प्रश्न का जवाब दे दीजिये कि आपने पहली पंक्ति में कहा कि जवाब तो मिला ही नहीं है और आप जवाब पढ़कर पूरक भी पूछ रहे हैं ।

श्री अनिल सिंह : रीटेन में माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया, मैं समझता था कि माननीय मंत्री सदन के अंदर जवाब देंगे ।

अध्यक्ष : यह सिस्टम ही इसीलिये किया गया है । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जहां तक सवाल है जुरीडिक्शन में अगर आपसी बंटवारा होता है तो फीस 50-50 रूपये लगते हैं । अगर उससे बाहर जाते हैं तो यह माननीय सदस्य जो कह रहे हैं इनको हमने कह दिया है कि एक दिन आईये, बैठकर हम टोटल समझा देंगे । 2012 का मामला अलग है और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा का मामला अलग है । दोनों अलग अलग है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि आईये हम बैठकर समझा देंगे ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा है.

श्री विजेन्द्र कुमार यादव, मंत्री : कानून में कुछ कंफ्यूजन है तो आपको भी कहेंगे कि आईये, कंफ्यूजन दूर हो जाये ।

श्री अनिल सिंह : माननीय मंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि इसमें कंफ्यूजन है । मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से मिल करके इस मामले का समाधान कराने का प्रयास करूंगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 2 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : 1. महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना ने फर्जी नामांकन के आधार पर प्रधानाध्यापकों द्वारा सरकारी योजना के करोड़ों रूपये के गबन की सूचना को अस्वीकार किया है ।

2. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि यू0डायस के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2015-16 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की कुल संख्या 2,19,43,818 थी जबकि सत्र 2016-17 में नामांकित छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 2,04,83,913 थी । इस प्रकार नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या में 14,59,905 की कमी शैक्षणिक सत्र 2016-17 में दृष्टिगत हुई । इसका मुख्य कारण आंकड़ों के संक्लन की प्रक्रिया में भारत सरकार के द्वारा परिवर्त्तन किया गया, जिसके तहत पूर्व में जहां छात्रों की संख्या का संकलन किया जाता था, वहीं शैक्षणिक सत्र 2016-17 से छात्रवार नामांकन की सूचना, जिसमें आधार संख्या भी सम्मिलित था, विद्यालयों से प्राप्त किया गया । फलस्वरूप छात्र-छात्राओं की सटीक संख्या की सूचना प्राप्त हुई । जहां तक नामांकन की संख्या में हुई उक्त कमी का संबंध राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से है, के क्रम में कहना है कि योजना का लाभ छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है । इससे योजनाओं की राशि के गबन का मामला स्थिर नहीं होता है ।

3. उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है कि 14 लाख से ऊपर फर्जी छात्र-छात्राओं की राशि की निकासी कर ली गयी है, जो छात्रवृत्ति पोशाक का 7,000/-रूपये की दर से दिया जाता है । महोदय, माननीय मंत्री जी के विभाग के जो लोग इसमें संलिप्त हैं, वही जवाब बनाकर माननीय मंत्री जी को दिया है और माननीय मंत्री जी उसे सदन में पढ़ दिये हैं । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब को मैं चुनौती देता हूं । महोदय, आप इसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से या सदन की कमिटी से करा दीजिये । दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा महोदय ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का सीधा आरोप था कि इसमें राशि का गबन किया गया है । जो भी योजनाओं का लाभ बच्चों को दिया जाता है, वह उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है, इसलिए जो उपस्थिति रहती है, उसी आधार पर होता है । इसलिए इसमें गड़बड़ी का कोई सवाल नहीं पैदा होता है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम माननीय मंत्री जी के जवाब से सहमत नहीं हैं । महोदय, स्पष्ट इसमें फर्जीवाड़े हो रहे हैं और एक जिला में नहीं, पूरे बिहार में हो रहे हैं और पूरे बिहार में हुए हैं । आप केवल तीन साल का 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 का जांच करा दीजिए ।

अध्यक्ष : यह जो मामला है, माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर यह बात सही है तो आप इसकी किसी वरीय निदेशक से, निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जो वरीय अधिकारी होते हैं, इसकी जांच करा दीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय,.....

अध्यक्ष : डायरेक्टर इसकी जांच करेंगे, डायरेक्टर से इसकी जांच हो जायेगी।

(व्यवधान)

डायरेक्टर वरीय अधिकारी होते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : डायरेक्टर से जांच होने दीजिए । अब तारांकित प्रश्न । माननीय सदस्य श्री जय वर्धन यादव । सीनियर डायरेक्टर आई0ए0एस0 अधिकारी होते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री जयवर्धन यादव ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री का इतना स्पष्ट जवाब है और उसके बाद भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और जब आसन का नियमन हो गया कि डायरेक्टर से इसकी जांच होगा तो आप किससे जांच कराना चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रधान सचिव से जांच करा दीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, जो डायरेक्टर जांच करके देंगे, उसकी समीक्षा प्रधान सचिव करेंगे ।

(व्यवधान)

आज सदन आप ही से मुखातिब है और रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपकी प्रशंसा विपक्ष के सभी माननीय सदस्य एक स्वर से कर रहे हैं । ये क्या अभी आने वाले प्रश्नों में पूरक पूछने में परिलक्षित होगा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, यह उनकी जर्रानवाजी है सर ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-1(श्री जय वर्धन यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, पालीगंज के नये भवन का निर्माण हो गया है । उसमें वर्ग कक्ष के संचालन हेतु उपस्कर आदि का Shifting किया जा रहा है । नवनिर्मित विद्यालय का वर्ग कक्ष Grill के अन्दर पूर्णतः सुरक्षित है । अतएव चाहरदिवारी के नहीं रहने के बावजूद नवनिर्मित भवन में वर्ग कक्ष संचालन में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री जय वर्धन यादव : महोदय, ये गर्ल्स हाई स्कूल है पालीगंज में और बाजार के बीच अवस्थित है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि चूंकि वहां छात्रायें पढ़ती है और छात्राओं में हमेशा असुरक्षा एवं भय का माहौल बना रहता है । ग्रील नहीं रहने से और चाहरदिवारी को खुला छोड़ देने से परिसर असुरक्षित रहता है । अतः हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि एक तय समय सीमा में चहारदिवारी का निर्माण सुनिश्चित करायें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2(श्री चन्द्रशेखर)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

इस क्रम में अवगत कराना है कि प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को संबंधित प्रधानाचार्य से विमर्श कर विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आधार पर अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण/जीर्णोद्धार की आवश्यकता आधारित प्राक्कलन तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय पत्रांक 366 दिनांक 08.02.2019 द्वारा दिया गया है ।

महोदय, इसमें काम कर रहे हैं और जब उसका प्राक्कलन आ जायेगा, उसके अनुसार काम करेंगे । यह प्रक्रियाधीन है और हम समझते हैं कि जल्द ही हो जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रकियाधीन है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, बहुत ज्यादा छात्र-छात्रायें हैं, उसके अनुपात में कमरा नहीं है तो कैसा विद्यालय चल रहा होगा ? हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कमरे का निर्माण सुनिश्चित कराया जाय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी देखेंगे कि शीघ्र बन जाय ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, यथाशीघ्र ।

तारांकित प्रश्न सं0-3(श्री राजेश कुमार)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विगत 6 माह से कभी नवीनगर के सी0डी0पी0ओ0 के प्रभार में रहते हैं और कभी सदर प्रखंड औरंगाबाद का रहते हैं । आप तत्काल कबतक सी0डी0पी0ओ0 का पदस्थापन कर देंगे, सिर्फ यही आश्वासन हम आपसे चाहते हैं ।

अध्यक्ष : उसका तो जवाब में तो लिखा हुआ है राजेश जी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से अधियाचना की गयी है, अभी नियुक्ति की भर्त्ती प्रक्रिया चल रही है, वह आते ही आपके यहां नियमित पदस्थापन दे दिया जायेगा । यह जवाब में ही है ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, अनुमान कबतक हो जायेगा ?

अध्यक्ष : कमीशन की प्रक्रिया है, वह तो समय लेती है ।

तारांकित प्रश्न सं0-4(श्री शिवचन्द्र राम)

श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में विकास मित्रों के स्वीकृत बल 9875 के विरूद्ध 9523 विकास मित्र कार्यरत हैं, शेष 352 विकास मित्रों का चयन प्रकियाधीन है । विकास मित्रों को प्रति माह दस हजार रूपये मानदेय दिये जाते हैं और उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । विकास मित्रों के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

श्री शिवचंद्र राम : अध्यक्ष महोदय, विकास मित्र महादलित समाज से आते हैं और पंचायत सेवक पंचायत में जितना मेहनत करता है, उससे कम विकास मित्र काम नहीं करता है । जितने भी पंचायत के विकास का मामला है, जिस प्रकार की सरकार की योजना हो, तमाम् चीजों का गिनती करने से लेकर विकास डेवलपमेंट, यहां तक कि चाहे जो भी सरकारी प्रोग्राम हो, उसमें वह ड्युटी करने का काम करता है, कोई महोत्सव लेकर । मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारा यह मानना है कि सरकार की महादलित, दलितों के प्रति ऐसी भावना है तो मात्र दस हजार रूपया में उसके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री शिवचंद्र राम : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या वह दस हजार रूपया में, आज के जमाने में मजदूर से भी कम रेट पर वह काम करने के लिए विवश है तो क्या सरकार दलितों के प्रति, महादलितों के प्रति कोई आस्था नहीं रखती है ? सरकार कहती है कि मामला विचाराधीन है । महोदय, सबका मानदेय बढ़ रहा है, सबका हो रहा है लेकिन विकास मित्र के लिए ऐसा क्यों ?

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री शिवचंद्र राम : महोदय, हम यह चाहते हैं कि सरकार मानदेय बढ़ाना चाहती है कि नहीं?

अध्यक्ष : सरकार ने तो कह दिया कि विचाराधीन नहीं है ।

श्री शिवचंद्र राम : नहीं तो, हमारा यह कहना है, इसपर हम कम-से-कम यह चाहते हैं कि सरकार इसपर विचार करके, चूंकि यह दलित का मामला है, इसपर आगे का कार्यक्रम बढ़ाये । महोदय, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, तारांकित प्रश्न सं0-5, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ।

(व्यवधान)

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

टर्न-3/राजेश/12.2.19

तारांकित प्रश्न संख्या: 5 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा प्रखंड के स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक-524 दिनांक 15.4.2017, पत्रांक-1372 दिनांक 8.12.2017, प्रथम स्मारण-73 दिनांक 18.1.2018, द्वितीय स्मारण-7079 दिनांक 11.4.2018, तृतीय स्मारण-10313 दिनांक 16.3.18, पत्रांक-1603 दिनांक 18.4.18, पत्रांक-221118 एवं पत्रांक-188 दिनांक 7.2.2019 द्वारा की गयी है । निर्विवाद सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड चौसा के अधीन रघुनाथ उच्च विद्या मंदिर, कलाशन है महोदय और वही पर सरकारी पोलिटेकनिक कॉलेज भी है, आई0टी0आई0 संस्थान भी है, मध्य विद्यालय भी है और बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ लगाते हैं, मैच होता है और सरकारी जमीन भी वहाँ पर उपलब्ध है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो प्राथमिकता सूची बनायी जायेगी स्टेडियम निर्माण के लिए, तो क्या उसमें रघुनाथ उच्च विद्या मंदिर, कलाशन को उसमें रखी जायेगी ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट रुप से सदन में कहा कि दिनांक 7.2.2019 को जिला पदाधिकारी से जमीन की अद्यतन स्थिति की मांग की गयी है, जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जायेगा, हम वैसे ही माननीय नरेन्द्र बाबू के यहाँ स्वीकृत कर देंगे ।

अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य को भी अनुरोध कर दीजिये कि जितना जल्द हो सके, वे जमीन उपलब्ध कराने में सहयोग करें ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री: महोदय, हम माननीय नरेन्द्र बाबू से आग्रह करते हैं कि हमारे कार्यालय से पत्रांक और दिनांक ले लें और वहाँ से जल्दी रिपोर्ट भिजवा दें ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 6 (माननीय सदस्य श्री भोला यादव)

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष: क्या है व्यवस्था बोलिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोषणा किया था स्टेडियम के मामले में पूरे बिहार में, हर प्रखंड मुख्यालय में, स्टेडियम का निर्माण करायेंगे, हम गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के............. (व्यवधान)

अध्यक्ष: वजीरगंज का जवाब अभी कहाँ से देंगे ।

श्री अवधेश नारायण सिंह: वे सूचना तो ले लें ।

अध्यक्ष: सूचना लेकर अभी क्या करेंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: हम अध्यक्ष जी को सूचना देते हैं, वे ग्रहण कर लेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । आप लिखित दे दीजियेगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष जी, मेरी बात को सुन लिया जाय । महोदय, वजीरगंज के टरमा में जमीन उपलब्ध है, कलक्टर रिपोर्ट भी भेज चुका है............

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, जब ये मंत्री थे, तो उस समय इनको चिंता नहीं था और जब ये मंत्री से विधायक हो गये, तब इनको चिंता हो रही है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब मैं मंत्री था, उस समय भी क्षेत्र की चिंता थी, तभी तो स्टेडियम का प्रस्ताव भेजे हुए हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 6 (श्री भोला यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-21199/13 एवं अन्य संलग्न वादों दिनांक 31.10.2017 को पारित आदेश के तहत संगत नियमावली के नियम 6 एवं 8 को रीड डाउन कर दिया गया है । उक्त न्यायादेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 नं0-20/18 दायर किया गया है, जिसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा गया है । इसके कारण प्रश्नगत कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन में विधिक कठिनाई है ।

विदित हो कि नवउत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का पद का सृजन एवं नियोजन होने तक संबंधित मध्य विद्यालय में कार्यरत अहर्ताधारी शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के संचालन का दायित्व दिया गया है ।

श्री भोला यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी हाईकोर्ट का हवाला देकर टाल रहे हैं प्रश्न को, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जब बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले लिये हैं, पढ़ रहे हैं, एक सेशन, दो सेशन निकल चुका है, उसके बावजूद हाईस्कूल के स्तर का कोई भी शिक्षक नहीं है, तो क्या मंत्री जी जब तक कोर्ट में यह मामला है, तो तब तक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखते हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूँ कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण कमी महसूस की जा रही है और इसके कारण..........(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप मूल प्रश्न को देखियेगा, तो माननीय सदस्य ने नियुक्ति की बात नहीं कही है, उन्होंने प्रश्न में ही प्रतिनियुक्ति की बात कही है, इसलिए आप इसको देख लीजिये और जिन विषयों में आवश्यकता है, कहीं स्पेयर, एक्स्ट्रा है, तो उन्हें दे दीजिये, प्रतिनियुक्त कर दीजिये ।

श्री भोला यादव: महोदय, मूल विषयों में एक भी शिक्षक नहीं है विद्यालयों में, ऐसी स्थिति में मैं तो सिर्फ दो का ही नाम दिया हूँ, अभी हमारे क्षेत्र में 24 विद्यालय है, किसी में शिक्षक नहीं है और जब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट जब खराब हो रहा है, कहीं भी वे कंपीटीशन के लायक नहीं निकल पा रहे हैं, ये बच्चे कोई और नहीं है, वे दलित, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनके साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है और सरकार हाईकोर्ट का हवाला देकर टाल रही है । महोदय, यह आम प्रश्न है ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, भोला बाबू ने प्रश्न को उचित उठाया है । महोदय, पूरे राज्य में यह स्थिति है । हमलोगों के क्षेत्र में भी यही स्थिति है । यदि सरकार शिक्षक की बहाली नहीं कर सकती है, तो सरकार के रहने का क्या औचित्य है महोदय ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, आपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण उन उच्च विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया है । चूंकि माननीय मंत्री ने स्वयं आगे बढ़ करके कहा है कि नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, तो अद्यतन स्थिति क्या है और कब तक कितने शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी ताकि इन उच्च विद्यालयों के साथ-साथ पूरे राज्य में रिक्त शिक्षकों के पद को भरा जा सके ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि वैधिक कठिनाई के कारण शिक्षकों का नियोजन बाधित है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक नियुक्ति संभव नहीं है, फिर भी सरकार उस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट टीचर के माध्यम से हम इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही कोर्ट का न्याय आ जायेगा, तो फिर भारी संख्या में नियुक्ति होगी और तब यह कमी पूरी हो जायेगी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने जो अवगत कराया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, तो इस स्थिति में इस सदन में यह स्पष्ट करना लाजिमी हो जाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया अद्यतन क्या है और कितनी नियुक्ति करने की अधियाचना आपने जो सक्षम प्राधिकार है, उसके पास भेजा है ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/12-2-19

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: चूंकि न्यायालय के फैसले का इंतजार है और हम मानते हैं कि शिक्षकों की कमी है । चूंकि नियुक्ति हो नहीं पा रही है, टी0ई0टी0/एस0टी0ई0टी0 बहुत से हमारे पास लोग हैं जिनको हम बहाल करना चाहते थे परन्तु न्यायालय में यह मामला फंसा हुआ है और बहुत जल्द उसका फैसला आने वाला है, बावजूद इसके हमलोग विभाग के स्तर से इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट टीचर की भी नियुक्ति कर रहे हैं और जहां जगह बताया जा रहा है, हम बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि वहां गेस्ट टीचर के माध्यम नियुक्ति कर शिक्षक उपलब्ध करा दें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, माननीय मंत्री नियुक्ति की प्रक्रिया की बात कह रहे हैं, मैं या सदन सिर्फ ये अवगत होना चाहता है कि कुल कितनी रिक्तयां हैं जिनके विरूद्ध आप नियुक्ति करने जा रहे हैं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: इसकी संख्या एडजेक्ट नहीं बतायी जा सकती है, उसका कारण है कि प्रश्न में भी यह नहीं है और दूसरी बात कि ये उत्क्रमण का कार्य तो लगातार चल रहा है और हमारा वादा है कि हम हरेक पंचायत में एक उच्च विद्यालय खोलने जा रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 2-3 बातों की ही जानकारी आपसे मांगी जा रही है । एक तो कितने पद रिक्त हैं, दूसरा कितने पदों पर नियुक्ति की अधियाचना दी गयी है और जो नियुक्ति से संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? अगर अभी सूचना उपलब्ध नहीं है तो मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । आप ये तीनों सूचनाएं उपलब्ध कराकर के सदन को दीजिये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय मूल प्रश्न में यह बात नहीं थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे, खासकर के जो माननीय सदस्य विपक्षी दल के हैं कि सदन को स्थगित कराकर के सरकार को मदद मत करिये ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी आपकी नजर बराबर उधर ही रहती है, इधर देखते ही नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-7(श्रीमती गुलजार देवी)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मध्य विद्यालय जिस पंचायत में है, वह माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत है । अतएव शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5-7-13 के आलोक में प्रश्नगत मध्य विद्यालय, परसा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा कराकर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय पत्रांक 410 दिनांक 11-2-19 द्वारा दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 8(श्री राम विलास पासवान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5-7-13 के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से अच्छादित करने का निर्णय संसूचित है । इसी संकल्प के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशालय स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा उत्क्रमण पर विचार किया जाता है ।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है । जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर अनुवर्त्ती कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, आवासीय बालिका विद्यालय है और वहां बच्चियां करीब 6 कि0मी0 पैदल एन.एच. पर जाती है पढ़ने के लिए सरमारी और उससे काफी दिक्कत है, कभी एक्सीडेंट का मामला हो सकता है । वहां पर तो बालिका आवासीय विद्यालय खोलना ही नहीं चाहिए जब उच्च विद्यालय नहीं था, वहां से करीब 6 कि0मी0 पढ़ने के लिए जाती है बच्चियां ।

अध्यक्ष: तो आप चाहते क्या हैं ?

श्री राम विलास पासवान: हम चाहते हैं कि वहां पर उच्च विद्यालय का निर्माण हो ।

अध्यक्ष: उच्च विद्यालय के लिए तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला स्तर पर समिति है वहां से अनुशंसा होकर के आती है तो यहां पर कार्रवाई होती है।

श्री राम विलास पासवान: तो ये कबतक हो जायेगा?

अध्यक्ष: जिला स्तर में ...

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के खंड-2 को देखा जाय । लड़कियां 6 कि0मी0 दूर से आती है, क्या बिहार सरकार वैकल्पिक व्यवस्था लड़कियों के आने जाने के लिए कर सकती है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, यह सर्वविदित है कि इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर के हर पंचायत में एक उ0वि0 के गठन की बात हमलोगों ने की है और घोषणा किया है और उस पर अमल भी हो रहा है । यह भी प्रक्रियाधीन है । हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसका भी उत्क्रमण हो जायेगा ।

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या प्रक्रियाधीन है, कितने वर्षों से लड़कियां 6 कि0मी0 दूरी तय कर के आ रही है, क्या बस वगैरह की व्यवस्था करेंगे ?

अध्यक्ष: सदानन्द बाबू सरकार साईकिल की व्यवस्था कर रही है, बस की व्यवस्था कहां कर रही है ।

श्री सदानन्द सिंह: साईकिल की भी व्यवस्था नहीं हो रही है..

अध्यक्ष: चलिये अवधेश बाबू क्या पूछना है पूछिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत स्पष्ट किया और मंत्री अपने वक्तव्य में कहें हैं कि पंचायत स्तर पर स्कूल का निर्माण करायेंगे और अभी सरकार ने निर्णय लिया है । महोदय, यह तो दो पंचायत की बात है, माननीय मंत्री जी को सदन में घोषणा करना चाहिए इन बच्चियों के कठिनाई को देखते हुए कि इस दो पंचायत के बीच में हम सरकारी हाई स्कूल का निर्माण करायेंगे । वे अपने वोले हैं मंत्री जी कि हर पंचायत में करायेंगे ...

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: आप तो दूसरे को पूछने के लिए दे चुके तो फिर क्यों आ गये ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: रामविलास जी, माननीय मंत्री जी आपने जिस विद्यालय के बारे में प्रश्न पूछा है उस पर उन्होंने कहा है कि वह प्रक्रियाधीन है, हमलोग विचार कर रहे हैं, जल्द हो जायेगा तो अब क्या सुनना चाह रहे हैं ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-9(श्री मुनेश्वर चौधरी)</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5-7-13 के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से अच्छादित करने का निर्णय लिया है। इसी संकल्प के निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला निर्दिष्ट समिति के समक्ष मध्य विद्यालय बोर्ड जो निर्धारित मापदंड को पूरा करता है, के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण के प्रस्ताव उपस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । जहां तक सदर प्रखंड, छपरा के मुसेपुर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रश्न है तो अंकित करना है कि उक्त पंचायत अन्तर्गत अवस्थित किसी भी मध्य

विद्यालय के पास निर्धारित मापदंड के अनुरूप 75 डिसीमल भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण तत्काल उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना में कठिनाई है ।

श्री मुनेश्वर चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सरकार बराबर कह रही है और अभी भी माननीय मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार का संकल्प है कि हर पंचायत में उच्च विद्यालय खोला जायेगा सरकार की इच्छा भी है (क्रमशः)

टर्न-5/मधुप/12.02.2019

श्री मुनेश्वर चौधरी : ..क्रमशः.. महोदय, लेकिन दुख के साथ कहता हूं कि सरकार अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर रही है और न ही उस रास्ता पर चल रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सदर प्रखंड छपरा के मुसेपुर पंचायत में जिस मिडिल स्कूल के प्रांगण में जमीन नहीं है और सरकार की इच्छा है उच्च विद्यालय खोलने की तो क्या सरकार उच्च विद्यालय को खोलने के हिसाब से और सरकार अपनी इच्छा को पूरा करने के ख्याल से वहां जमीन का अधिग्रहण कर उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? नम्बर वन ।

गरखा प्रखंड के गरखा पंचायत में जहां हाई स्कूल नहीं है, महोदय, जो जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है, उसको प्रक्रियाधीन को पूरा करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहाॅ जमीन उपलब्ध नहीं है और उसी पंचायत में अगर कोई दूसरा मध्य विद्यालय चल रहा है, उसके पास अगर जमीन उपलब्ध है तो प्राथमिकता के आधार पर वहाॅ बनाया जा सकता है । अगर किसी भी विद्यालय के पास जमीन नहीं है तो इस मामले में हम माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि वे भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करा दें, हम बहुत जल्द उसका उत्क्रमण करा देंगे ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, यह बिल्कुल उल्टी बात लगती है । तब सरकार अपने रास्ते पर चलने का संकल्प पूरा नहीं कर रही है । सरकार की इच्छा है कि राज्य के हर पंचायत में हम हाई स्कूल खोलेंगे । यदि जहां जिस पंचायत में हाई स्कूल खोलने के लिए जमीन नहीं है, सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्यों नहीं जमीन का अधिग्रहण करके हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ? मैंने प्रश्न पूछा है कि जिन पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का सरकार विचार रखती है, उन पंचायतों में हाई स्कूल खोलने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है तो सरकार जमीन का अधिग्रहण करने का विचार रखती है ? यह मैंने सवाल किया है ।

अध्यक्ष : पूछ रहे हैं कि अभी जमीन अधिग्रहण करने का कोई विचार है या नहीं है तो बताइये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : जमीन की उपलब्धता हो जाएगी तभी न इसको किया जायेगा !

अध्यक्ष : वह तो बात हो गई, जमीन अधिग्रहण करने की कोई योजना है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : नहीं है ।

अध्यक्ष : नहीं है तो बताइये न ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : अवधेश बाबू, आज लगता है कि एक प्रश्न भी प्रश्न को आप खाली नहीं जाने दीजिएगा या कि आप मंत्री जी से कुछ जिलावार सांठ-गांठ है ? यह कुछ गया कनेक्शन लगता है।

(व्यवधान)

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, मेरा प्रश्न अभी बाकी है । मैं अभी खड़ा हूं ।

अध्यक्ष : अभी प्रश्नकर्त्ता ही खड़े हैं ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, मेरे सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी नही दे पाये । सरकार का इरादा बिल्कुल झूठा और गलत है । सरकार चाहती है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल खोलेंगे, बार-बार मंत्री जी कहते हैं ।

अध्यक्ष : मुनेश्वर बाबू, आप क्या जानना चाहते हैं ? सरकार ने तो बता दिया कि अधिग्रहण करके विद्यालय खोलने की कभी कोई नीति नहीं बनी है । अब आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, तब सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई कि सरकार भुलावे की बात करती है। जहां विद्यालय में जमीन नहीं है और सरकार जमीन को अधिग्रहण करने के लिए......

अध्यक्ष : अभी तो उन्होंने कहा है कि पहले आप भी मिलकर प्रयास करिये कि जमीन उपलब्ध हो जाय ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, जमीन की व्यवस्था करने का काम प्रश्नकर्त्ता का है या सरकार का है?

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-10 : श्री अचमित ऋषिदेव । शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान)

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, हम अभी खड़े हैं ।

अध्यक्ष : आप खड़ा हैं तो कितना प्रश्न पूछियेगा ?

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, जमीन का अधिग्रहण करने का या जमीन की व्यवस्था करने का काम प्रश्नकर्त्ता का दूसरी पंक्ति का है । पहली पंक्ति का काम सरकार का है । क्या सरकार जमीन अधिग्रहण के इस काम को करना चाहती है ?

अध्यक्ष : किसी ने आपको कहा कि आपकी जिम्मेवारी है यह ?

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, उन्होंने कहा ।

अध्यक्ष : जो किसी ने कहा ही नहीं, जबर्दस्ती क्यों जिम्मेवारी ले रहे हैं ?

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, हम नहीं ले रहे हैं, उन्होंने कहा ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इधर देखिये और अब श्री अचमित ऋषिदेव जी के प्रश्न का जवाब दीजिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 10 (श्री अचमित ऋषिदेव)</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला अन्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कोशिकापुर दक्षिण पंचायत के ग्राम-गरेरिटोला प्राथमिक विद्यालय बॉसटोला में 256 छात्र/छात्राओं का नामांकन है । नामांकन के अनुसार 5 शिक्षक कार्यरत हैं ।

ज्ञातव्य हो कि विद्यालय में औसत उपस्थिति 145-150 रहती है, जिसके अनुरूप शिक्षक पर्याप्त पदस्थापित हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-11 (श्री भाई वीरेन्द्र)</u>

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, आप तो मानते हैं कि शिक्षा मंत्री बड़े अच्छे हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : इसलिए मानता हूं कि हमारी तरफ आने वाले हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : इस प्रश्न में आपको उत्तर मिल जायेगा ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न उन्होंने आपके लिए जॉच परीक्षा रखा है कि आप इनको कितना चाहते हैं, इसी प्रश्न के उत्तर से पता चलेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हुजूर, इनसे कान में बात करते हैं, खुलेआम बात करते नहीं हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । मनेर विधान सभा का अधिकांश क्षेत्र दानापुर अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, जहॉ पूर्व से ही अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में बी0एस0 कॉलेज, दानापुर, महिला महाविद्यालय, खगौल, दानापुर, जे0एल0एन0 कॉलेज, खगौल, दानापुर संचालित है ।

मनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : अब कान में बतिया लीजियेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मनेर सूफी-संतों की धरती है और गंगा-जमुनी संस्कृति का संगम है। वहॉ डिग्री महाविद्यालय नहीं है, 19 पंचायत है, 19 वार्ड है, वहां नगर पंचायत है और उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सब लोग आई0ए0 करके फिर छोड़ देता है, तो उस प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू में ही कहा कि अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय खोलने की सरकारी नीति है और इसपर हमलोग काम भी कर रहे हैं ।

प्रखंड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय खोलने का अगर कोई निर्णय भविष्य में लिया जायेगा तो मैं मनेर को प्राथमिकता दूंगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हुजूर, सरकार को कोई इसपर विचार करना चाहिए कि जिन प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय नहीं हैं, वहॉं खोला जाय । सरकार जो घोषणा की है उसके अनुरूप भी सरकार नहीं चल रही है और यह भी काम करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि शिक्षा के प्रति सरकार रूचि नहीं लेती है, केवल बजट उसमें डालती है और उस पैसे को निकाल कर अपने चुनाव सभा में लगाती है ।

अध्यक्ष : खैर, आपकी जो भी बात हो लेकिन माननीय मंत्री जी की नजर में आपका विधान सभा क्षेत्र प्राथमिकता में है, जो उन्होंने कहा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, आपके माध्यम से हम एक बात और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर वहां पर डिग्री महाविद्यालय खोला जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 12 (श्री रामदेव राय)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का निर्णय बोर्ड के स्तर से किया जाना है । इसी क्रम में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1556 दिनांक-07.12.2018 द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पद पर स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जा चुकी है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, प्रभार में जो अध्यक्ष होते हैं, उनके जिम्मे प्रबंध समिति गठन करने का अधिकार नहीं है क्या ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि अभी तो स्थायी नियुक्ति हुई है, उसके पहले कोई प्रभार में होंगे, तो जो प्रभार में रहते हैं उनको प्रबंध समिति गठन करने का अधिकार होता है या नहीं होता है ? अभी उनका गठन न जल्दी करा दीजिये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : कोई पार्टिकुलर विद्यालय की बात इसमें नहीं कही गई है लेकिन अब जब अध्यक्ष आ गये हैं तो निश्चित रूप से जहां इसके गठन की आवश्यकता होगी, वहां प्राथमिकता के आधार पर गठन करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, अभी जहां-जहां आवश्यकता होगी, उसकी बात नहीं है । अभी माननीय सदस्य के एक विद्यालय का प्रश्न है कि इसमें जल्दी बनवा दीजिये, वह न कहिये । अभी तो एक विद्यालय का प्रश्न है ।

टर्न-6/आजाद/12.02.2019

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, अब तो इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी, प्रारंभ हो जायेगी और इसमें प्राथमिकता के आधार पर इस विद्यालय में बनवा दिया जायेगा ।

श्री रामदेव राय : प्राथमिकता किसको कहते हैं, आप इतने पुराने आदमी हैं, प्रबंध समिति वर्षो से नहीं है, विद्यालय संचालन में दिक्कत हो रही है, संस्कृत शिक्षा के प्रति सरकार उदासीन क्यों है ? यहां पर आप तुरंत गठन कराईए, आज चाहियेगा तो आज गठन हो जायेगा, इसमें क्या लगा हुआ है । वहां के जो विधायक हैं, उनको अध्यक्ष बनाईए और उस विद्यालय के जो डोनर हैं, उनको सदस्य बनाईए । क्या लगा हुआ है, इसमें क्या कठिनाई है ? नीयत खोट है तो कैसे बनाईयेगा । प्रबंध समिति नहीं है और न प्रबंध समिति को कोई अधिकार देते हैं, उठकर बोलिये ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, संस्कृत विद्यालयों में माननीय विधायकों को मनोनयन का पहले से कोई इस तरह की बात नहीं है । लेकिन अब जब अध्यक्ष पूर्णकालिक हो गये हैं तो हम इसपर विचार करेंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है ।

श्री रामदेव राय : देखिए हुजूर, देखिए ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का जवाब हुआ क्या ? आप स्वयं संतुष्ट हैं क्या ? एक प्रबंध समिति की गठन की बात है, दो महीने पहले इनके अध्यक्ष नियुक्त हुए, उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क के लिए ये क्या बात कर रहे हैं ? इनका तीन वर्ष-साढ़े तीन वर्ष बीत चुका है विधायक का, ये क्या बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह प्रबंध समिति के गठन का मामला है, आप एक महीना में गठन करवा दीजिए ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-13(श्री उपेन्द्र पासवान)</u>

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रश्न के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय खोले जाने के निमित भवन निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है । जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को संदर्भित महाविद्यालय के लिए चयनित भूखण्ड को हस्तांतरित करने/नई भूमि लीज नीति के तहत भूमि क्रय करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया है । जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत भूमि हस्तांतरण कराने की कार्रवाई की जायेगी एवं तदोपरांत भवन निर्माण किया जा सकेगा ।

श्री उपेन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भूमि का प्रस्ताव न्यास बोर्ड को भेजा गया था ठाकुरबाड़ी के जमीन के संबंध में और इस आशय की जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया था कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से न्यास बोर्ड की जमीन को, ठाकुरबाड़ी की जमीन को न्यास बोर्ड में भेजा गया है और इसपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठाकुरबाड़ी की जमीन के संदर्भ में बोले थे कि कॉलेज जहां खुला है.....

अध्यक्ष : न्यास बोर्ड को जो भेजा गया था, क्या न्यास बोर्ड ने उसकी स्वीकृति दी ?

श्री उपेन्द्र पासवान : जी, नहीं । इसमें माननीय मंत्री महोदय कहीं कोई दिलचस्पी नहीं लिये, जिसके कारण न्यास बोर्ड ने इसको अस्वीकृत कर दिया ।

अध्यक्ष : अस्वीकृत कर दिया तब ।

श्री उपेन्द्र पासवान : इस आशय की जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया कि बखरी में अब भूमि अधिग्रहण के सिवा कोई उपाय नहीं है डिग्री कॉलेज खोलने के लिए ।

अध्यक्ष : तो उपेन्द्र जी, भूमि अधिग्रहण करके डिग्री कॉलेज खोलने या हाइस्कूल खोलने के सिद्धांत पर अभी हमलोगों ने 10 मिनट चर्चा किये हैं कि सरकार की कोई योजना नहीं है ।

श्री उपेन्द्र पासवान : वह अलग है, उत्क्रमित विद्यालयों के लिए अलग व्यवस्था है महोदय । डिग्री कॉलेज नया है और सभी अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है और इसमें भूमि अधिग्रहण करने की भी बात मंत्री महोदय बोल चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण करने का भी प्रस्ताव है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी को लिखा गया है और जिला पदाधिकारी.....

अध्यक्ष : पूछने दीजिए, सिद्दिकी साहेब भी पूछ लेते हैं तो एक साथ जवाब दे दीजियेगा ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : पूछ लीजिए भी आप ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाईए उपेन्द्र जी, आपका चांस खतम हो गया, अब आप आराम से बैठ जाईए न ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, सरकार का नीतिगत निर्णय है कि वैसे अनुमंडल जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां सरकार डिग्री कॉलेज खोलेगी । अब सरकार डिग्री कॉलेज कैसे खोलेगी, जमीन अधिग्रहण करेगी, जमीन उपलब्ध करायेगी, यह जमीन की अनुपलब्धतता के बारे में नहीं कह सकते हैं, चूँकि यह कॉलेज वैसे अनुमंडल जहां एक भी कॉलेज नहीं है, वहां सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कॉलेज खोलने का, इसलिए सरकार को ही खोलना है तो सरकार कैसे खोलेगी, कितने दिनों में खोलेगी, यह बताये?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सिद्दिकी साहेब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह हमारी चिन्ता होनी चाहिए .....

अध्यक्ष : आप इनके बारे में दो-चार लाईन और बोलिए न कि वरीय सदस्य हैं, पुराने सदस्य हैं, सबकुछ समझते हैं, यह सब बोलिए ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, यह सब तो आप बोल दिये, यह तो हम बोलने जा ही रहे थे । महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से नीतिगत फैसला है कि हम हर अनुमंडल में जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी स्तर से डिग्री कॉलेज खोलवायेंगे, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और इसपर अमल भी हो रहा है । पार्टिकुलर बेगूसराय का

जहां तक सवाल है, इसका फैसला नीतिगत लिया जा चुका है कि वहां डिग्री कॉलेज खोलना है और जिला पदाधिकारी को इसके लिए लिखा गया है कि आप अपने स्तर से व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर के भूमि की उपलब्धतता सुनिश्चित कीजिए ताकि वहां जल्द से जल्द भवन का निर्माण कराया जाय । हम समझते हैं कि आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी तसल्ली करा देते हैं कि जिला पदाधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया गया है, लिखा गया है और आज हम पुनः कार्यालय जाकर के उनसे बात करके इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द से सारी बाधाओं को दूर करते हुए यहां भूमि की उपलब्धतता करायी जाय ।

अध्यक्ष : अब तो मंत्री जी ने जिस दुलर्भ विश्वास के साथ कहा है, उसपर तो आपको मान जाना चाहिए ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, मैं तो सरकार को मदद कर रहा हूँ कि सरकार की नीति कैसे जल्द से जल्द इम्पलीमेंट हो मगर सरकार नीति बनाकर, अगर उसको इम्पलीमेंट नहीं करती है तो कोरी घोषणा ही न कही जायेगी ?

श्री उपेन्द्र पासवान : महोदय, ...

अध्यक्ष : आपको तो उसी समय कह दिये थे, अब रामदेव जी को पूछने दीजिए न । आप माईक अपनी तरफ और घुमाईए ।

श्री उपेन्द्र पासवान : महोदय, वहां अधिकांश आबादी दलित, अति-पिछड़ों, पिछड़ों की आबादी है और खासकर वहां के छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि वहां पर एक इन्टर कॉलेज है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में भवन उपलब्ध है तो क्या माननीय मंत्री महोदय तब तक डिग्री कॉलेज की पढ़ाई उसमें सुनिश्चित कराना चाहते हैं या नही ? जब तक भवन का निर्माण नहीं हो पाता है, तब तक डिग्री कॉलेज की पढ़ाई इस इन्टर कॉलेज में हो ?

श्री रामदेव राय : महोदय, बेगूसराय के बारे में चर्चा चल रही है, बखरी की तरह सेम बात तेघड़ा के लिए है । तेघड़ा अनुमंडल में कोई कॉलेज नहीं है, इसलिए इसमें तेघड़ा को भी संलग्न कर लीजिए ताकि कलक्टर से इसके बारे में मंगवा लीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको भी देखवा लीजिए ।

डॉ0 अभय कुमार सिन्हा । समाज कल्याण विभाग का उत्तर दिया हुआ है, आप पूरक पूछिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-14(श्री अभय कुमार सिन्हा)

श्री अभय कुमार सिन्हा : सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करेंगे कि इसमें मिसप्रिन्ट हुआ है, हम डॉक्टरेट नहीं किये हुए हैं, इसमें डॉ0 अभय कुमार सिन्हा लिखा हुआ है, इसको सुधार कर लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल टेकारी विधान सभा से संबंधित था, उसमें स्पष्ट किया गया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र के कितने भवन बने हुए हैं, कितने भवन बनाये गये हैं और कितने भवन बनाये गये हैं वो शौचालयविहिन हैं और पेयजलविहिन हैं । यह हमारा सवाल था महोदय, लेकिन सवाल में स्पष्ट नहीं किया गया है कि टेकारी विधान सभा में कितने रूपयों का आवंटन किया गया है । .... क्रमश: ......

टर्न-7/शंभु/12.02.19

तारांकित प्रश्न सं0-14 का पूरक

श्री अभय कुमार सिन्हा : क्रमश:....मई में 93 लाख गया जिला को भवन बनाने के लिए दिया गया और जून 2018 में 62 लाख 36 हजार रूपया पेयजल और शौचालय के लिए गया जिला को दिया गया तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि गया जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन है और कितने आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया गया है, लेकिन वह पेयजल और शौचालयविहीन है ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हुजूर........

अध्यक्ष : हम समझ गये कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि 12 बज गया । इसलिए प्रश्नकाल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें । अब कार्य-स्थगन ।

कार्य-स्थगन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 12 फरवरी, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है । श्री सत्यदेव राम, श्री सुदामा प्रसाद एवं श्री महबूब आलम दूसरा श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्री समीर कुमार महासेठ । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय-व्ययक का उपस्थापन वित्तीय कार्य 2018-19 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन एवं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं उसपर वाद-विवाद का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-

(व्यवधान)

आप सुने तो नहीं कुछ ? क्या रसोइयों को, अरे आप पहले सुनिए तो या खाली खाना पर ही ध्यान रहता है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-176(3) एवं 6(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

अरे अब शून्यकाल है आप ही लोगों का है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, आज जो स्थिति है कम से कम सूचना तो सुन लिया जाय । आज जो स्थिति है जिसपर कार्य-स्थगन है । आज राज्य में कानून-व्यवस्था चौपट हो गयी है, स्थिति ऐसी भयावह है कि दिन-दहाड़े व्यापारी, किसानों, आम नागरिकों से लूटपाट एवं उनकी हत्याएं, अपहरण तथा छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं । महोदय, राज्य सरकार अपराधियों से सख्ती से नहीं निपट रही है, राज्य के अन्य हिस्से को छोड़ दिया जाय तो पटना में मुख्यमंत्री एवं आला अधिकारियों के नाक के नीचे जघन्य अपराध, लूट-खसोट एवं हत्याएं हो रही है । महोदय, हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि अब मोबलिंचिंग भी बिहार में पांव पसारने लगा है- व्यापारियों से लूट, उनकी हत्या जैसे वारदात अखबार की सुर्खियों में हमेशा छपते रहे हैं । महोदय, हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि कार्य-स्थगन यह लोकहित में है । इसलिए सभी कार्यों को स्थगित करके इसपर विमर्श कराने की आवश्यकता है । महोदय, इन विषयों पर विमर्श कराना अति आवश्यक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका शून्यकाल भी है उसमें पढ़ियेगा, स्थिर रहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय......

अध्यक्ष : शून्यकाल श्री विनोद प्रसाद यादव ।

(व्यवधान)

अरे अब शून्यकाल आ रहा है तो आप क्यों खड़े हैं ? अब बैठिए, अब शून्यकाल है।

<u>शून्य-काल</u>

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड में इंदिरा नगर एवं महम्मदपुर के सामने बूढ़ी नदी में पुल नहीं रहने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है । जनहित में इंदिरा नगर एवं महम्मदपुर के सामने बूढ़ी नदी में समरसिबुल पुल निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के उत्तरी भाग में 8 एवं 9 फरवरी, 2019 को भारी ओलावृष्टि के कारण कई पंचायतों में किसानों का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है । किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

श्री अमित कुमार : सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड के नरहा पंचायत ढाव टोला में बागमती की पुरानी धारा में पुल का निर्माण नहीं होने से हजारों ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । सरकार जनहित में उक्त स्थल पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र करावे।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, पुरातत्ववेत्ता, मुद्राशास्त्री, पुरालिपिज्ञाता, धर्मशास्त्री, प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्र ज्ञाता, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, चीनी, प्राकृतिक, पाली आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता महान स्वतंत्रता सेनानी डा0 काशी प्रसाद जायसवाल के नाम पर आयकर चौक अथवा पटना दूरदर्शन के निकट चौक के नामकरण करने की मांग करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, बिहार के सभी जिले से शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के कर्मियों ने 9 फरवरी, 2019 से लगातार पटना के गर्दनीबाग में अपने बच्चों के साथ कई मांगों को लेकर आमरण-अनशन पर बैठे हैं तथा उनकी स्थिति चिंताजनक हो गयी है । अत: सरकार से उनकी मांगों को मानते हुए अनशन समाप्त कराने की मांग करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : सिवान जिलान्तर्गत दरौली (सु0) क्षेत्र सं0-107 के दरौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं होने और इलाके से जिला मुख्यालय की 40 कि0मी0 दूरी होने की वजह से बच्चे और खासकर बच्चियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । अतएव दरौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी जो सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत आता है द्वारा नवम्बर, 2017 में सचिवालय के विभिन्न विभागों में आइ0टी0 प्रबंधकों को संविदा पर नियोजन हेतु गेट स्कोर के आधार पर 150 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया था । सरकार अविलंब पैनल के सभी अभ्यर्थियों को बहाल करे ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत नयागांव थाना कांड सं0-09/19, 20.01. 2019 में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के चलते पीड़ित गंगासागर राय चीनी व्यवसायी परिवार सहित आत्मदाह को उतारू है । अतएव उक्त कांड की अविलंब जॉच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई एवं व्यवसायी को पैसा वापस दिलाने की मांग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 18 हजार रूपया मानदेय सहित अन्य 15 सूत्री मांगों को लेकर विगत 7 जनवरी से विद्यालय रसोइयों की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण स्कूलों में मिड-डे मील योजना पूरी तरह प्रभावित हो गयी है । रसोइयों की मांगे मानते हुए इस हड़ताल को अविलंब समाप्त करवाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री नीरज कुमार : महोदय, खगड़िया जिला के पी0आर0आनंद, उम्र-15 वर्ष, पिता- श्री मनोज कुमार मंडल, दिनांक 11.12.18, थाना कांड सं0-890/18, चित्रगुप्त नगर, खगड़िया को कंचन लॉज, अशोक नगर वार्ड नं0-15 से लापता हैं । पुलिस आज तक उस व्यक्ति की खोज नहीं कर पायी है । मैं कार्रवाई की मांग करता हूं । यह गंभीर मामला है महोदय...

अध्यक्ष : आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं, आप पूर्णरूप से ठीक कह रहे हैं । आप अत्यंत सही बात बोल रहे हैं । अब तो बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है । सड़क दुर्घटना में आम लोगों के साथ वाहन चालक की मृत्यु होती है । आम लोगों में बचपन से जागरूकता पैदा करने के लिए ट्रैफिक नियम के विषय को बिहार स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना । श्री श्याम रजक एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

टर्न-8/ज्योति/12-02-2019

ध्यानाकर्षण सूचना

सर्वश्री श्याम रजक, लाल बाबू राम एवं अन्य नौ सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम रजक, अपनी सूचना पढ़ें ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0- 9706, दिनॉक 20-07-2018 की कंडिका-5(।।।) में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी प्रोन्नतियॉं मूल कोटि के वरीयता के स्थान पर फीडर कैडर की वरीयता के आधार पर देय होगी, तत्संबंधी विभागों द्वारा सूची प्रकाशित की गयी है । लेकिन पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने ही बनाये वरीयता सूची को नजरअंदाज कर अनुसूचित जाति / जन जाति के वरीयतम पदाधिकारियों को छोड़कर अपेक्षाकृत कनिष्ठों (सामान्य श्रेणी) को प्रोन्नति दी गयी है । इससे अनुसूचित जाति/ जन जाति के पदाधिकारी प्रोन्नति के लाभ से वंचित हो गए हैं ।

अतएव संकल्प के विपरीत दी गयी प्रोन्नतियों को रद्द कर अनुसूचित जाति/ जन जाति के पदाधिकारियों को प्रोन्नत करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, दो विभागों से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए समय चाहिए ताकि दोनों में समन्वय बैठाकर जवाब दे सकें ।

सर्वश्री आलोक कुमार मेहता, भोला यादव एवं अन्य दो सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार मेहता पढ़ें- नहीं हैं, श्री भोला यादव..., श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, चलिए आ गए हैं तो माननीय सदस्य शाहीन जी सूचना पढ़ें ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन: महोदय, वर्ष 2011-12 में STET परीक्षा में उत्तीर्ण हुए एवं 2016 में पंचम चरण शिक्षक नियोजन में बिहार के विभिन्न जिलों के उत्क्रमित विद्यालयों की रिक्ति नहीं जोड़ने के कारण अभ्यर्थी नियोजन से वंचित रह गए । राज्य में लगभग 5700 उत्क्रमित माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहे हैं जबकि उत्क्रमित होने साथ ही उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन -पाठन में दिक्कत आ रही है साथ ही परीक्षाफल गिरता जा रहा है। वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण STET प्रमाण पत्र की वैद्यता तथा अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्ति पर है ।

अत: वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के STET प्रमाण पत्र की वैद्यता की समयावधि बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में 5520 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय अवस्थित हैं । वर्ष 2011 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा

उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र की वैद्यता प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि, जो माह जून 2012 था, से 07 (सात) साल निर्धारित है ।

राज्य के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 19502 माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजन की कार्रवाई की जा रही थी, इसी बीच समान काम समान वेतन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खण्डपीठ के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या -21199/2013 एवं अन्य संलग्न याचिकाओं में दिनॉक 31-10-2013 को आदेश पारित करते हुए उक्त नियमावली के नियम-6 एवं 8 को उत्पति के समय से ही read down कर दिया गया है । उक्त न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या 20/2018 दायर किया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई सम्पन्न कर फैसला सुरक्षित रखा गया है । वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभागीय संकल्प सं0-51 दिनॉक 25-01-2018 द्वारा पठन पाठन हेतु अतिथि शिक्षक की सेवा ली जा रही है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायादेश पारित होने के उपरान्त ही नियोजन की पात्रता सहित अन्य विषयों पर निर्णय लेते हुए अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर पहले भी सदन में जवाब दिया था । 7 वर्षों का समय बितने को है, 31 मार्च 2019 को जो STET प्रमाण पत्र की वैद्यता समाप्त होने वाली है माना कि सरकार माननीय न्यायालय के न्यायादेश के इंतजार में है, ये सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं और यह उनके हाथ में नहीं है कि उसका कुछ कर सके लेकिन सरकार के हाथ में एक चीज अवश्य है कि इतने सारे छात्र जो STET की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनकी वैद्यता की अवधि बढ़ाये ताकि आने वाले दिनों में जो वैकेन्सी आएगी और उसमें उनको निश्चित रुप से उसका मौका मिले, सरकार सिर्फ कोर्ट का बहाना बनाकर छात्रों को शिक्षकों से वंचित नहीं रख सकती । शिक्षक नहीं रहने से आधे से अधिक छात्र फेल कर रहे हैं । माननीय मंत्री ने विधान परिषद् में भी इसका जवाब दिया था लेकिन जो स्थिति है पूरे बिहार में अभी से प्रश्न काल में भी जितने सवाल उठे मैं समझता हूँ कि सारे सवालों में, ये सवाल हर जगह डौमिनेट कर रहा है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, सरकार से मांग है, हमारे पूरे सदन की, मेरी समझ से कि 2011-12 में पास STET की जो वैद्यता है उसको बढ़ाया जाय और तबतक बढ़ाया जाय जबतक न्यायादेश न आ जाय और प्रक्रिया पूरी न हो ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो न्यायालय की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लम्बा समय भी लगेगा एक तो इसकी मान्यता बढ़ाईये और

दूसरा अतिथि शिक्षक जो बहाली करने जा रहे हैं उनकी जगह पर इन लोगों पर बहाल कर लीजिये जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जायेंगे और जब न्यायालय का आदेश आयेगा तो उस पर रेगुलर कर दीजियेगा सैंक्शन पद पर तो अतिथि शिक्षक के बहाली का सरकार विचार रखती है ?

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिन सवालों को माननीय सदस्य यहाँ उठा रहे हैं इस संदर्भ में वैसे शिक्षकों का डेलीगेशन भी हमसे बराबर मिलते रहता है और यह बात सचमुच में बहुत उचित लगता है कि जिन लोगों ने परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की और वैद्यिक कठिनाईयों के कारण उनका नियोजन नहीं हो पा रहा है और समय बीतता जा रहा है लेकिन अभी चूँकि थोड़ा वक्त है इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरुरत नहीं है । न्यायालय का फैसला किसी भी क्षण आ सकता है लेकिन इस संबंध में जो आपने कहा है अतिथि शिक्षक के पद पर STET अभ्यर्थियों को बहाल करने का, उसपर हम बाद में बोलेंगे, हम व्यक्तिगत रुप से भी अपने अधिकारियों के साथ कई बार इस संबंध में बैठक कर हमने इस प्रश्न का हल सुलझाने का प्रयास किया है और शिक्षक लोग जिनका समय खत्म होने वाला है उनको फिर एक्सटेंशन दिया जाय या आगे फिर क्या कार्रवाई की जाय इस सबंध में हमलोगो की बात चल रही है । सबसे बड़ी एक कठिनाई इसमें यह है कि माननीय सदस्य को बतलाना चाहूँगा कि STET जो है उसका तो यह राज्य सरकार के अधीन है लेकिन TET में केन्द्र सरकार की सहभागिता होती है तो हम अगर STET के साथ कोई कंसीड्रेशन कर भी लें तो TET हम केन्द्र सरकार को लिख सकते हैं उनसे अनुरोध कर सकते हैं लेकिन संपूर्ण विषयों पर हमलोग बहुत संवेदनशील हैं सरकार की पूरी चिन्ता है कि उनको समय रहते ही नियोजन की कार्रवाई हो जाय और उनका समय जो हे वो नष्ट नहीं हो इसके लिए हमलोग गंभीर हैं और इसपर निरंतर हमलोग सोच रहे हैं कोई न कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे ।

श्री भोला यादव : महोदय, अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति करने पर सरकार को क्या कठिनाई है किसी न किसी को तो आप बहाल करेंगे ही तो इसको तो घोषणा कर दीजिये अध्यक्ष महोदय के समक्ष, वो हम जब तक ये नहीं होता है इनकी अवधि बढ़ा देंगे और अतिथि शिक्षक के पद पर इनको हम तत्काल नियुक्त करने जा रहे हैं ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : सदानंद बाबू आप तो अध्यक्ष रहे हैं ।

श्री सदानंद सिंह : हम नहीं पूछना चाहते हैं नियम भी नहीं है ।

अध्यक्ष : जब आप नियम तोड़ कर पूछना चाहते हैं तो पूछिये ।

श्री संदानंद सिंह : नियम नहीं है लेकिन यह बड़ा संवेदनशील मामला है पात्रता शिक्षक लोगों ने ग्रहण कर ली है और न्यायालय के चक्कर में इनलोगों की समय सीमा समाप्त हो रही

है तो संवेदशील मामला है और राज्य हित का मामला है इसलिए बेराजगार युवकों को कंसीडर करना चाहिए ।

अध्यक्ष : इसीलिए तो दोनों माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, दोनों सुझाव उपयुक्त है और सरकार ने कहा है कि हम उसपर विचार करेंगे ।

क्रमशः

टर्न-9/12.02.2019/बिपिन

अध्यक्ष : क्रमशः माननीय मंत्री जी, दोनों सुझाव उपयुक्त है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः बिल्कुल । हमलोग खुद इससे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं लेकिन यह जो भोला बाबू का सुझाव आया है कि गेस्ट टीचर में उनको प्राथमिकता दी जाए, यह बिल्कुल सही सुझाव है और निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि गेस्ट टीचर की जो नियुक्ति आगे होगी, हमलोग उसपर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष : उसपर विचार करेंगे ।

(थपथपी)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः दोनों हाथ से बजाइए न !

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, मैं सरकार को इस निर्णय के लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन...

अध्यक्ष : लेकिन ऐसा मत कुछ कहा लीजिए कि फिर बात पलट जाए ।

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, मूल प्रश्न यह है कि अभी मात्र सवा महीना बाकी है उनकी मियाद पूरी होने में, मेरा यह कहना है कि सवा महीना के अंदर केंद्र सरकार से बात करना हो, राज्य सरकार को जो भी निर्णय लेना हो, दस-पंद्रह दिन के अंदर यदि नहीं लेती है सरकार तो बिहार के हजारों-हजार शिक्षक जो टी.ई.टी.-एस.टी.ई.टी. पास कर चुके हैं उनका भविष्य अधर में होगा और माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया गंभीरता से लेते हुए आज से ही इस काम को प्रारंभ किया जाए ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न : 10/कृष्ण/12.02.2019

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रभारी मंत्री । वित्त विभाग ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक व्यय विवरण सदन में उपस्थापित करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या (2) अधिनियम, 2018, बिहार विनियोग संख्या (3) अधिनियम, 2018, बिहार विनियोग संख्या (4) अधिनियम, 2018 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूं ।

बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं । माननीय सदस्यगण, सुशासन, भ्रष्टाचार एवं अपराध पर जीरो टॉलरेंस, सामाजिक सुधार आंदोलन, मुख्यमंत्री के सात निश्चय, प्रधानमंत्री का बिहार पैकेज तथा आई0 टी0 का सुशासन में प्रयोग कर बिहार ने देश में एक अलग पहचान बनायी है । आज देश के कई राज्य बिहार के अनेक कार्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं। बिहार के बारे में अब कहा जा सकता है कि What Bihar thinks today, India thinks tomorrow. बिहार जो आज सोचता है, कल हिन्दुस्तान उसको सोचता है ।

वैश्विक अर्थ-व्यवस्था, भारत की अर्थ-व्यवस्था तथा बिहार की अर्थ-व्यवस्था के रूझान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने के निर्णय, यूरोपीय देशों की कमजोर होती अर्थ-व्यवस्था, जलवायु परिवर्त्तन जैसी चुनौतियों के कारण, वैश्विक अर्थ-व्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है । वर्ष 2018 के उत्तरार्द्ध में वैश्विक अर्थ-व्यवस्था की विकास दर 3.7 प्रतिशत रही और विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष

2019 में विकास दर 3.5 परसेंट रह जायेगी । इस निराशाजनक विश्व के परिदृश्य के बावजूद भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विकास दर 2017-18 में 7.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2018-19 में 7.5 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है । आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्था है । वर्ष 2013-14 में भारत जहां 11वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था थी, वहीं आज वह छठी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था है । यदि वर्तमान विकास दर जारी रहा तो 2015 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनियां की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था बन जायेगी ।

महोदय, बिहार का वित्तीय प्रबंधन अनेक राज्यों से बेहतर है, CRISIL ने अपने रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है । इस पृष्ठभूमि में बिहार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन द्वारा अर्थ-व्यवस्था के सभी प्रमुख मानकों यथा-ग्रोथ रेट, Fiscal Deficit, Revenue surplus, ऋण प्रबंधन, राजस्व व्यय और ब्याज व्यय का अनुपात, डेवलपमेंटल और नॉन-डेवेलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर देश के अनेक राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है । रेटिंग एजेंसी CRISIL की केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट - Report States of growth 2.0 के अनुसार वर्ष 2017-18 में 11.3 प्रतिशत के विकास दर के साथ देश के सभी राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है ।

महोदय, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक क्रमशः बिहार के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है । पंजाब का ग्रोथ रेट केवल 6.2 तथा केरल 5 विकास दर के मामले में अंतिम पायदान पर है । CRISIL Report के अनुसार निर्माण, मनुफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन ये सर्वाधिक रोजगार पैदा करनेवाले क्षेत्र हैं । इन क्षेत्रों का ग्रौस ऐडेड वैल्यू का प्रत्येक राज्य का आकलन किया गया, जिसमें गुजरात, बिहार, हरियाणा का विकास वर्ष 2013 से 2018 के बीच सर्वाधिक रोजगार पैदा करनेवाला पाया गया । वर्ष 2013-18 में बिहार का रोजगार का ग्रौस ऐडेड वैल्यू का आंकड़ा 8.2 है । केन्द्र के 7 से ज्यादा है और पूरे देश में बिहार गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है । तात्पर्य यह कि बिहार का विकास दर रोजगार पैदा करनेवाले क्षत्रों में सर्वाधिक है । महोदय, 2017-18 में कंज्यूमर प्राईस इन्डेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी बिहार की खुदरा मंहगाई दर अखिल भारतीय 3.6 की तुलना में 2.7 है । जहां केरल की मंहगाई दर 6 है, तमिलनाडू 4.9, महाराष्ट्र 4.1 की तुलना में बिहार का खुदरा मंहगाई दर मात्र 2.7 है । वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2018 में बिहार उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में मंहगाई दर में सर्वाधिक गिरावट देखी गयी है ।

महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत परिव्यय यानी राज्य स्थाई संपत्ति के निर्माण पर अपने कुल खर्च का कितना खर्च करता है । CRISIL ने पाया कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच अपने कुल खर्च में पूंजीगत व्यय 28.8 परसेंट है । यानी आप जो पूरा

खर्च करते हैं उसमें सड़क, बिल्डिंग, डैम, पुल-पुलिया जिसको पूंजीगत परिव्यय कहते हैं उस पर आप कितना खर्च करते हैं तो बिहार का यह 28.8 परसेंट है । जो केरल के 9, बंगाल के 10.3 और महाराष्ट्र के 11.5 के लगभग दोगुना है ।

, CRISIL Report में बिहार ग्रामीण क्षेत्र में खर्च करने में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है और गृह निर्माण में तीसरे स्थान पर है । बिहार किन क्षेत्रों में किस क्रम से खर्च करता है । रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च करता है । उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर, तीसरे स्थान पर सड़क एवं पुल, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण खर्च के मामाले में चौथे पायदान पर तथा स्वास्थ्य पांचवें स्थान पर है । महोदय, यह तो था CRISIL की रिपोर्ट के आधार पर ।

अब रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया प्रत्येक वर्ष राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक दस्तावेज प्रकशित करती है । तो आर0बी0आई0 की नजर में बिहार का वित्तीय प्रबंधन । आर0बी0आई0 का स्टेट फाईनेन्स स्टडी ऑफ बजट, 2017-18 एण्ड 2018-19 के अनुसार बिहार की राजस्व प्राप्तियां यानी बिहार की जो आमदनी है, वर्ष 2016-17 में मात्र 8.6 प्रतिशत ब्याज भुगतान पर खर्च किया गया । यह प्रतिशत 2017-18 में 7.3, 2018-19 में 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है । जबकि पश्चिम बंगाल अपने आमदनी का 18 प्रतिशत केवल ब्याज पर खर्च करता है । पंजाब 18.8 परसेंट, हरियाणा 16.5 प्रतिशत और गुजरात 15 प्रतिशत अपने आमदनी का केवल ब्याज पर खर्च करता है और बिहार केवल अपने आय का, रेवेन्यू रिसिट का 7.3 प्रतिशत ब्याज भुगतान पर खर्च करता है । यानी राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज का व्यय पर प्रतिशत अधिकांश राज्यों से बेहतर है । 14वीं फायनेंस कमीशन ने अनुशंसा की थी कि किसी भी राज्य का ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का अधिकतम 10 परसेंट तक रहना चाहिए । लेकिन बिहार का मात्र 7.3 प्रतिशत है । महोदय, आर0बी0आई0 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यानी विकासात्मक व्यय वर्ष 2016 से 2017-18 के बीच लगभग 70 प्रतिशत रहा है। गैर विकासात्मक व्यय केवल 25 से 26 परसेंट रहा है । महोदय, राजस्व प्राप्तियों से राजस्व खर्च वहन करने के पश्चात् जो शेष बचत है, उसको रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है । जब रेवेन्यू सरप्लस होता है तो उसका उपयोग कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी असेट निर्माण में खर्च किया जाता है । वर्ष 2008-09 से बिहार लगातार रेवेन्यू सरप्ल राज्य बना हुआ है । वर्ष 2012-13 के 5,101 करोड़ के मुकाबले 2017-18 में 14,823 करोड़ तथा 2018-19 में 21,311 करोड का रेवेन्यू सरप्लस है । आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, राजस्थान, पंजाब ये रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स हैं । यानी इन राज्यों को वेतन, पेंशन के लिये भी कर्ज लेना पड़ता है ।

महोदय, 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच में रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट को 1 लाख 94 हजार करोड़ रूपया देने की अनुशंसा की है । आंध्र को राजस्व घाटे के कारण 22 हजार करोड़ प्राप्त होगा, केरल को 9,519 करोड रूपया, बंगाल का 11 हजार 760 करोड़ रूपया प्राप्त होगा । यानी बिहार को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार 1 लाख 94 हजार करोड़ अनुदान कके हिस्से से वंचित रह जायेगा । अगर हम भी घाटे में रहते तो केन्द्र से पैसा ज्यादा मिल जाता । लेकिन हम घाटे में नहीं है। इसलिये पंजाब, बंगाल, केरल राज्यों को 1 लाख 94 हजार करोड़ मिला और हम उससे वंचित रह गये ।

क्रमशः

टर्न-11/अंजनी/दि0 12.02.2019

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः ...क्रमशः.... महोदय, सामाजिक प्रक्षेत्र पर व्यय के मामले में भी बिहार कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजारात जैसे राज्यों से आगे है । 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को राजपोषीय घाटा (Fiscal Deficit) जी0एस0डी0पी0 का 3 प्रतिशत की सीमा में रखने की अनुशंसा की है । मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार का राजकोषीय घाटा एक वर्ष को छोड़कर लगातार तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर है । महोदय, वर्ष 2005-06 में राज्य पर कुल बकाया ये जी0एस0डी0पी0 का 56 प्रतिशत था, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2017-18 में कुल बकाया 1लाख 56हजार करोड़ है, जो जी0एस0डी0पी0 का मात्र 32.15 प्रतिशत था । महोदय, जहां 2005-06 में हमारा बकाया 56.36 परसेंट था, वह घटकर 32.15 प्रतिशत रह गया है ।

महोदय, प्रति व्यक्ति के आय के मामले में वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2017-18 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 28,425 रूपये थे, जो राष्ट्रीय औसत के 86,668 रूपये का 32.9 प्रतिशत है । वर्ष 2015-16 में और 2016-17 में लगातार बिहार की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का फासला लगातार घटता जा रहा है । महोदय, 11परसेंट की विकास दर के साथ देश में सर्वाधिक विकास दर हासिल करने के बावजूद कुछ लोगों को विकास नजर नहीं आता है, इसलिए महोदय किसी ने कहा है कि

नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं,
दिशा को बदलो तो किनारे
खुद-ब-खुद बदल जाते हैं ।

महोदय, शराबबंदी में मिली सफलता के बाद बाल विवाह तथा दहेज प्रथा के विरूद्ध सामाजिक जन अभियान को भी जदर्बस्त जन समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार ने शराबबंदी को कारगर बनाने हेतु आई0जी0, मद्य निषेध की नियुक्ति कर टॉल फ्री नम्बर सार्वजनिक किया गया है । इसपर कोई भी व्यक्ति अवैध शराब से जुड़ी सूचना दे सकता है । महोदय, बेलट्रोन स्थित मद्य निषेध लोक आसूचना केन्द्र पर 12 मार्च से 7 फरवरी, 2019 तक 14,758 शिकायतें दर्ज हुई है और वर्त्तमान में 3,268 लोग जेल में बंद हैं । महोदय, शराबबंदी जैसा कठिन निर्णय ने सरकार ने गरीबों की जिन्दगी को बदल दिया है । जो लोग शराबबंदी का मजाक उड़ाते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा -

नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है,
मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी ।

अध्यक्ष महोदय, आपने गिराने का काम किया और नीतीश जी ने लोगों को संभालने का काम किया है । महोदय, बाल विवाह में भी बिहार में काफी कमी आयी है। एन0एफ0एच0एस0-3 का सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 में किया गया था, के अनुसार बिहार में 47.8 प्रतिशत बाल विवाह के साथ देश में पहले नम्बर पर था परन्तु दस वर्षों के बाद एन0एफ0एच0एस0-4 के सर्वे में बिहार में बाल विवाह में 20 प्रतिशत की कमी पायी गयी है । महोदय, वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक एवं अन्य संस्थाओं द्वारा 11 विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है ।

महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 180 प्रतिभागी देशों की 100 से अधिक परियोजनाओं में से जीविका परियोजना यानी स्वयं सहायता समूह की जो जीविका परियोजना है, उसको ग्रामीण विकास में इनोवेसन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व बैंक प्रेसीडेंट अवार्ड प्रदान किया गया है । महोदय, वर्ष 2016-17 के लिए बिहार को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मक्का उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार देने की घोषणा हुई है । महोदय, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा डेयरी एवं पशु प्रक्षेत्र में सतत उच्च वृद्धि एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए बिहार को ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशीप अवार्ड,2018 प्रदान किया गया है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कौशल युवा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु स्कॉच डेवलपमेंट फांउडेशन, नई दिल्ली द्वारा 51वीं नेशनल स्कॉच कान्फ्रेंस में बिहार को दो कौशल विकास पुरस्कार यथा स्कॉच और्डर ऑफ मेरिट अवार्ड और स्कॉच गोल्ड फोर स्किल डेवलपमेंट अवार्ड से नवाजा गया है । महोदय, जी0एस0टी0 में बिहार की योगदान को देखते हुए श्री अरूण कुमार मिश्रा, अपर सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फोर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 2018 से सम्मानित किया गया है । महोदय, पटना

सिटी बस सेवा को केन्द्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा बेस्ट सिटी बस इनिसियेटिव अवार्ड, 2018 से पुरस्कृत किया गया है ।

महोदय, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ष 2018-19 में बिहार मंडप को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्श एवं उत्कृष्ट मंडप के लिए स्वर्ण पदक से नवाजा गया है । महोदय, बिहार आगे भी इसी प्रकार पुरस्कार प्राप्त करते रहेगा । हम रूकने वाले नहीं हैं और किसी कवि ने कहा है कि-

खग ! उड़ते रहना जीवन भर,
मत डर प्रलय झकोरों से तू,
बढ आशा हलकोरों से तू,
क्षण में यह अरि-दल मिट जायेगा,
तेरे पंखों से पिसकर,
खग ! उड़ते रहना जीवन भर ।

महोदय, मैं बजट 2019 पर आता हूँ । बिहार राज्य बजट का आकार वर्ष 2004-05 में 23,885 करोड़ रूपये था और अब वर्ष 2019-20 में नौ गुणा से अधिक बढ़कर, मैं सदस्यों को बताना चाहूंगा कि बिहार में रेकर्ड 2 लाख करोड़ का बजट हम पेश करने जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2004-05 का जो बजट था, उससे 9 गुणा ज्यादा है और यह रेकर्ड 2,00,501 रू0 का बजट पेश है। महोदय, 2019-20 में जो प्लान है, उसको वार्षिक स्कीम कहते हैं, यह 1 लाख करोड़ है जो प्लान एक्सपेंडीचर है जो वर्ष 2005-06 में 6 हजार करोड़ था, उसको 16 गुणा बढ़ाकर एक लाख करोड़ पर हमलोगों ने प्लान एक्सपेंडिचर किया है । महोदय, वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 99 हजार 110 करोड़ रूपया है । महोदय, 2005-06 में प्लान एक्सपेंडिचर कुल खर्च का 21 परसेंट था और नन प्लान 78 परसेंट, प्लान केवल 21 परसेंट लेकिन 2019-20 में यह बराबर-बराबर हो गया । यानी प्लान 21 परसेंट से बढ़कर 50 परसेंट पर पहुंच गया कुल खर्च का और नन प्लान घटकर 50 परसेंट पर रह गया है ।

.....क्रमशः......

टर्न-12/राजेश/12.2.10

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, 2019-20 में कुल पूंजीगत व्यय यानि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट पर कितना हम खर्च कर रहे हैं, एसेट निर्माण पर तो लगभग हम 45270 करोड़ रुपये का अनुमान है जो कुल खर्च का 22.58 प्रतिशत है । महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व व्यय एक लाख 55 हजार करोड़ रुपये अनुमानित

किया गया है, जो कुल व्यय का 77.42 प्रतिशत है । महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 88157 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, इसमें वेतन पर 24538 करोड़ प्राईमरी से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षको, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के वेतन अनुदान पर 24064 करोड़, संविदा कर्मियों के वेतन पर 3138 करोड़, पेंशन हेतु 18457 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 10723 करोड़ और ऋण वापसी पर 7235 करोड़ यानि कुल मिलाकर 88157 करोड़ हम वेतन, वेतन के लिए अनुदान, पेंशन आदि पर हम खर्च करेंगे । महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के अपने श्रोतों से नन-टैक्स रेवेन्यू के रुप में 4806 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें खनन से 1600 करोड़ रुपया और ब्याज प्राप्तियों से 2293 करोड़ रुपया शामिल है, उसी प्रकार 2019-20 में ऑन टैक्स रेवेन्यू के रुप में 33800 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें 25500 वाणिज्यकर से, 4700 स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से, ढ़ाई हजार करोड़ परिवहन से एवं 1100 करोड़ रुपया भू-राजस्व से प्राप्त होगा । अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 24420 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है । महोदय, 14वें फाइनान्स कमीशन की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7414 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त होगा, जिसमें पंचायतों के लिए 6368 करोड़ और नगर निकायों के लिए 818 करोड़ रुपया शामिल है । महोदय, पॉचवे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों को 3751 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, इसमें 70 परसेंट राशि पंचायत निकायों को अर्थात् 2226 करोड़ और 30 परसेंट राशि नगर निकायों को अर्थात् 1125 करोड़ रुपया दिया जाना प्रस्तावित है । महोदय, केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2019-20 में 89121 करोड़ अनुमानित है । महोदय, 2019-20 में राज्य को केन्द्र से सहायक अनुदान के रुप में 49019 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। महोदय अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राशि कर्णांकित की गयी है तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जातियों के लिए 17928 करोड़ एवं अनुसूचित- जनजातियों के लिए 1840 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है । महोदय, वर्ष 19-20 में सबसे ज्यादा खर्च हम शिक्षा पर करने वाले हैं, महोदय, 34798 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जायेगा । राज्य की सड़कों पर 17923 करोड़, लगभाग 18 हजार करोड़, ग्रामीण सड़कें एवं पथ निर्माण की सड़कों पर खर्च किया जायेगा, उर्जा पर 8894 करोड़, स्वास्थ्य पर 9622 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग पर 15669 करोड, पंचायती राज पर 12206 करोड़ और गृह विभाग पर यानि पुलिस पर 10968 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, राज्य के 24 जिलान्तर्गत 280 प्रखंडों के सूखाग्रस्त किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना हेतु 1430 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है, इसके तहत 16 लाख 76 हजार किसानों से प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 13 लाख 73 हजार किसानों के खाते में

901 करोड़ रुपया ट्रान्सफर कर दिया गया है । महोदय, वर्ष 2018-19 में सिंचाई के लिए साढ़े तीन सौ रुपया ....

श्री सत्यदेव राम: बटाईदारों के लिए तो बताइये ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यकंत्री: इसमें यह मैं बता दूं कि यह दोनों के लिए है, बटाईदार और गैर बटाईदार शायद आपको मालूम नहीं है । वर्ष 18-19 में सिंचाई के लिए साढ़े तीन सौ रुपया प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान को बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है और अध्यक्ष महोदय खरीफ हेतु 19 लाख किसानों से प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 15 लाख 66 हजार किसानों को 171 करोड़ किसानों को डीजल अनुदान उनके खाते में भेजा जा चुका है और महोदय बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना है तथा धान, मक्का एवं रब्बी में अधिसूचित फसलों में वास्तविक उपज दर से 20 प्रतिशत से कम तक ह्रास की स्थिति में सात हजार रुपया और 20 प्रतिशत से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर अधिकतम दो हेक्टेयर तक भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, खरीफ 18 के लिए 11 लाख 50 हजार से ज्यादा किसानों ने अपना निबंधन कराया है, जिसमें 5 लाख 15 हजार रैयत किसान हैं और छ: लाख 35 हजार गैर रैयत यानि बटाईदार हैं यानि 11 लाख 50 हजार में अध्यक्ष महोदय रैयत है 5 लाख 15 हजार और बटाईदार हैं छ: लाख 35 हजार और रब्बी के लिए अभी तक दो लाख 32 हजार किसानों ने और निबंधन कराया है । महोदय फसल कटनी संबंधी प्रतिवेदन ऑन लाईन पोर्टल में प्रवृष्टि 28 फरवरी, 19 तक करने के पश्चात् सहायता राशि की गणना कर लाभुकों को मार्च, 2019 में भुगतान किया जायेगा। महोदय, 18-19 में 318 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, साथ ही महोदय, 2018 की तुलना में जनवरी, 2019 में भू-जल स्तर में पॉच फीट से लेकर 1 फीट तक औसत में कमी पायी गयी है । सुखाड़ प्रभावित जिलों में युद्धस्तर पर 24732 चापाकल की मरम्मती कर चालू किये गये, 6026 चापाकल की मरम्मती की जा रही है तथा पूरे राज्य में एक लाख 31 हजार चापाकलों को मरम्मत कर चालू कर दिया गया है । महोदय, सरकार केवल आदमी की ही चिंता नहीं करती है बल्कि जानवरों की भी चिंता करती है और राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भी पानी की चिंता की है, 14 जिलों में 146 कैटेल ट्रफ का निर्माण प्रगति पर है तथा 110, अन्य 226 स्थानों पर 15 मार्च तक निर्माण पूरा कर लिया जायेगा । महोदय, केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानि पी0एम0 किसान सम्मान के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 6 हजार प्रति परिवार देने का निर्णय लिया है । बिहार में 96 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत हैं, जिनको इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक पिछले 24 घंटे में 90 हजार से ज्यादा किसानों ने पी0एम0 किसान इस पोर्टल पर निबंधन करा चुके हैं बिहार के अंदर । महोदय, वर्ष 19-20 में राज्य में जैविक खेती

की सब्जी को बढ़ावा देने हेतु कृषि इनपुट अग्रिम अनुदान की राशि को छः हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपया किया जायेगा । महोदय, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना के अन्तर्गत 8413 पैक्सों को 20 लाख प्रति पैक्स कृषि यंत्र खरीदने के लिए 1692 करोड़ की योजना स्वीकृत की है । महोदय, कृषि रोडमैप, पहला कृषि रोडमैप और दूसरा कृषि रोडमैप, तो जहॉं चावल उत्पादन में बिहार 8वें स्थान पर था, अब बिहार छठा स्थान पर पहुंच गया है, वही मक्का में बिहार पॉचवें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी रोडमैप के पूर्व एवं द्वितीय रोडमैप के दौरान 4.57 से बढ़कर 7.55 प्रतिशत हो गयी है, मक्का में 7.70 से बढ़कर 14.7 प्रतिशत, सब्जी 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गया है । महोदय, आज सब्जी उत्पादन में बिहार पूरे देश में तीसरा एवं फल उत्पादन में छठा स्थान पर है, हम आलू में तीसरे नं0 पर है, बैगन, हरी मिर्च, मूली में हम चौथे नं0 पर है, लीची और मखाना उत्पादन में हम एक नं0 पर है, अमरुद में तीसरे है, आम में पॉचवे है एवं केला में 8वें स्थान पर है । महोदय, इस प्रकार जहॉं वर्ष 2017 में भीषण बाढ़ का मजबूती से मुकाबला करने के उपरान्त सुखाड़ की चुनौतियों का सामना करते हुए हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहूंगा ....(व्यवधान)

(इस अवसर पर सी0पी0आई0एम0एल0 के सभी मा0सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन किये)

टर्न-13/सत्येन्द्र/12-2-19

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री(क्रमशः): उसी प्रकार बिहार के अन्दर सुखाड़ का भी हम मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने कहा है- हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, नहरों से डरकर नैया पार नही होती, नैया पार नहीं होती । (व्यवधान) महोदय, मैं कह रहा था जिस तरह से बाढ़ का मजबूती से हमलोगों ने मुकाबला किया उसी तरह 2018 के सूखे का भी मुकाबला कर रहे हैं । किसी ने कहा- हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, नहरों से डरकर नैया पार नहीं होती । महोदय, जगमगाता बिहार कभी अंधकार में डूबे तथा लालटेन, ढ़िबरी, मोमबती की रोशनी में जिंदगी व्यतीत करने वाले बिहार के सभी 39 हजार 73 गांवों, 1 लाख 6 हजार 249 टोलों तथा 32 लाख 49 हजार इच्छुक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन समय सीमा के दो माह पहले बिजली पहुंचाने में बिहार देश का आठवां राज्य बन गया है । महोदय, 2019 के दिसम्बर तक 5827 करोड़ रू0 व्यय कर पृथक कृषि फीडर से सिंचाई हेतु बिजली पहुंचाने एवं 2827 करोड़ की लागत से 71 हजार 672 कि0मी0 खराब एवं जर्जर तारों को बदलने की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य प्रारम्भ हो

गया है और 31 दिसम्बर के पहले पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है कि हम बिहार में सभी कृषि फीडर लगा देंगे और सभी जर्जर तारों को बदल देंगे और महोदय अगले दो वर्षों में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा सिंचाई हेतु मात्र 75 पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्त्ति की जायेगी । वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार ऊर्जा प्रक्षेत्र पर 8 हजार 894 करोड़ रू0 खर्च करेगी । महोदय, पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में कुल 17923 करोड़ रू0 2019-20 में व्यय किया जायेगा । पथ निर्माण विभाग द्वारा 13064 कि0मी0 पथों का सात वर्षों के लिए अनुरक्षण हेतु अनुमानित 6654 करोड़ रू0 खर्च किये जायेंगे। मतलब वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3533 करोड़ की लागत से बगरा घाट पुल, चकिया केसरिया सत्तर घाट पुल, गंडक नदी पर धनहा रतवल घाट पुल, अगुवानी घाट पुल, पटना शहर स्थित लोहिया चक्र पथ सहित अनेक परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है । महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 5286 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना पर 2815 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला सम्पर्क योजना पर 1035 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है । टोला सम्पर्क योजना हेतु नाबार्ड से बाजार दर पर 500 करोड़ का ऑफ बजट लोन भी प्राप्त हुआ है । अध्यक्ष महोदय, विश्व की सबसे बड़ी यह जो बालक और बालिका साईकिल योजना दुनिया की सबसे बड़ी साईकिल योजना है । महोदय, विश्व की सबसे बड़ी बालक और बालिका साईकिल योजना के तहत 2018-19 तक 1 करोड़ 27 लाख छात्र छात्राओं को साईकिल खरीदने हेतु पैसा दिया जा चुका है । महोदय, 2018-19 में साईकिल हेतु 2500 की राशि को बढ़ाकर 3000 किया जा चुका है । महोदय, वर्ष 2019-20 में 4 लाख 59 छात्रों, 5 लाख 15 छात्राओं हेतु 292 करोड़ का प्रावधान किया गया है । महोदय, कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं के पोशाक हेतु 1000 रू0 की राशि को बढ़ाकर 1500 रू0 करते हुए 11 लाख 56 हजार छात्रों हेतु 173 करोड़ रू0 आवंटित किया गया है । छात्राओं के सेनेटरी नेपकीन की राशि को भी 150 की राशि को बढ़ाकर 300 रू0 करते हुए 2018-19 में 56 करोड़ 20 लाख आवंटित किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु इंटरमीडियेट में उत्तीर्ण 2 लाख 49 हजार अविवाहित छात्राओं को 10 हजार की दर से 249 करोड़ रू0, स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 25 हजार रू0 प्रति छात्रा की दर से 300 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, डिजीटल क्रांति पुलिस से पंचायत तक, अब बिहार की अधिकांश सेवाएं आई0टी0 के माध्यम से दी जा रही है । राज्य की सभी योजनाओं के लाभुकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है । वर्ष 2018-19 में 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 7733 करोड़ रू0 उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। महोदय, 270 करोड़ की लागत से

क्राईम ऐंड क्रीमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम अन्तर्गत सभी 894 थानों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराकर 6 लाख एफ0आई0आर0 पोर्टल पर डाला जा चुका है । अप्रैल, 2019 तक पटना और नालंदा जिला और सितम्बर, 2019 तक पूरे राज्य में थानों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो जायेगा । सी0सी0टी0एन0 के माध्यम से नागरिक अपना एफ0आई0आर0 ऑनलाईन दर्ज कर सकेंगे । सभी अपराधियों का रेकर्ड, गुमशुदा नागरिकों के मामले, दर्ज एफ0आई0आर0 की ट्रेकिंग आदि द्वारा अपराध पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा । महोदय, पटना शहर की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 लगाने हेतु 110 करोड़ की योजना और स्वीकृत की गयी है । महोदय, बिहार के 6105 ग्राम पंचायत और 354 प्रखंडों में ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क बिछाया जा चुका है और भारत नेट द्वारा गांव में हाई स्पीड ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा रही है । 700 ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर प्रारम्भ किया गया है, जहां कॉमन सर्विस सेंटर को पांच हजार रू0 बिजली के लिए और 3000 रू0 रखरखाब के लिए दिया जा रहा है और आगे आने वाले 6 महीने के अन्दर सभी ग्राम पंचायतों के अन्दर ये कॉमन सर्विस सेंटर काम करने लग जायेंगे । महोदय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 250 क्षमता की मेडिकल शिक्षा तथा 5000 बेड का विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने हेतु 5540 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है । आयुष्मान भारत के अन्दर राज्य के 1 करोड़ 8 लाख लाभुक परिवारों को 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा हेतु 550 सरकारी एवं 52 गैर सरकारी अस्पतालों को सुचीबद्ध करते हुए 2 लाख 51 हजार लाभुकों को गोल्डन कार्ड वितरित किया जा चुका है । वर्ष 2019-20 में आयुष्मान भारत हेतु 335 करोड़ का प्रावधान किया गया है । महोदय, 2019-20 में राज्य में केन्द्र-राज्य सरकार द्वारा 11 नये मेडिकल कॉलेज छपरा, पूर्णियां, समस्तीपुर, बेगुसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, भोजपुर एवं जमुई में निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । महोदय, यह सरकार युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है । स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में अपने तरह की अनुठी योजना है, इसमें बैंकों के बजाय राज्य कोष से छात्रों को 4 प्रतिशत और छात्राओं और दिव्यांगों को 1 प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण दिया जा रहा है, 1 फरवरी, 2019 तक 34717 छात्रों को 959 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा 2019-20 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 833 करोड़ का और प्रावधान किया गया है । महोदय, मुख्यमंत्री का निश्चय था कि हरेक जिले में एक-एक इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में एक पोलिटेकनिक महिला आई0टी0आई0 तथा सभी अनुमंडलों में एक-एक आई0टी0आई0 प्रारम्भ करने के मुख्यमंत्री निश्चय के तहत अभी तक 19 कार्यरत इंजीनियरिंग कॉलेज में 10700 छात्र एवं 33 जिलों में 39 कार्यरत पोलिटेकनिक में 20 हजार 720 छात्र अध्ययनरत है । इसी प्रकार राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में 101 आईटी0आई0 में 19 हजार 916 छात्र नामांकित हैं तथा 38 महिला आई0टी0आई0

में 2103 विद्यार्थी नामांकित हैं । इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, राज्य के 190 तकनीकी सरकारी संस्थानों में 53 हजार 509 लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं । महोदय, ये सरकार कमजोर तबकों के लिए प्रतिबद्ध है । राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदायों के आर्थिक शैक्षणिक विकास के लिए कटिबद्ध है। इस वर्ष इन वर्गों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जिसके लिए यू0पी0एस0सी0, बी0पी0एस0सी0 के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को 1 लाख रू0, 50 हजार रू0 छात्रावास अनुदान योजना के अन्तर्गत 1 हजार रू0 प्रति माह अनुदान तथा खाद्यान्न आपूर्त्ति योजना के अन्तर्गत 15 किलो अनाज प्रतिमाह निःशुल्क आपूर्त्ति की जा रही है। इसी प्रकार एस0सी0, एस0टी0 उद्यमी योजना अन्तर्गत 5 लाख रू0 अनुदान एवं 5 लाख रू0 ब्याज रहित ऋण उद्योगों को लगाने के लिए और मुख्यमंत्री परिवहन योजना अन्तर्गत प्रति पंचायत इन वर्गों के पांच युवकों को वाहन दिया जा रहा है ।(क्रमशः)

टर्न-14/मधुप/12.02.2019

...क्रमशः...

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री सात निश्चय के अन्तर्गत हर घर नल-जल योजना अंतर्गत फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं लौह प्रभावित क्षेत्रों तथा गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति हेतु 2019-20 में पी0एच0इ0डी0 द्वारा 3684 करोड़ रूपया खर्च किया जायेगा जिसमें मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत 1950 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पेयजल एवं पक्की नली-गली योजनान्तर्गत 2018-19 में 1925 करोड़ रू0 एवं 2019-20 में 1925 करोड़ रू0 तथा का प्रावधान किया गया है ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता अभियान अन्तर्गत शौचालय का आच्छादन जहां वर्ष 2014 में 22 प्रतिशत था वह बढ़कर 99.49 प्रतिशत हो चुका है और अभी तक बिहार में कुल 1 करोड़ 17 लाख शौचालय बनाये जा चुके हैं । इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 5016 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में 4950 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

महोदय, इस तरह के निश्चय करने के लिए हिम्मत चाहिए । बिना हिम्मत के इस तरह का निश्चय नहीं हो सकता है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, ठीक ही कहा है -

''तीर खाने की अगर हवस है तो जिगर पैदा कर,
सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर ।''

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के अन्तर्गत जैन, कांवरिया, मंदार एवं अंग प्रदेश परिपथ हेतु 200 करोड़ की योजना के विरूद्ध 122 करोड़ रू0 खर्च किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त महाबोधि कल्चरल सेन्टर, बोधगया में 2500 क्षमता

के ऑडिटोरियम हेतु 145 करोड़ रू0, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप हेतु 300 करोड़ तथा पुनौराधाम सीतामढ़ी में माँ जानकी की जन्मस्थली पर रामायण परिपथ हेतु केन्द्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं ।

महोदय, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत 17,887 करोड़ रू0 की लागत से प्रथम चरण में दानापुर से मीठापुर तक कुल 16.94 कि0मी0 एवं द्वितीय चरण में पटना जंक्शन से अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल तक 14.45 कि0मी0 मेट्रो रेल हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसपर 2019-20 में कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

महोदय, इको टूरिज्म अन्तर्गत राजगीर वन्य प्राणी आश्रयणी अन्तर्गत 191 हेक्टेयर में 176 करोड़ रू0 की लागत से जू सफारी का निर्माण कराया जा रहा है । राजगीर में ही 500 हेक्टेयर में 19 करोड़ रू0 की लागत से नेचर सफारी तथा वेणू वन के उन्नयन हेतु 27 करोड़ रू0 व्यय कर निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है ।

महोदय, संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 करोड़ 98 लाख की लागत से 140 सीटों की क्षमता वाला 3डी थियेटर जिसमें वन्य जीवन से संबंधित चलचित्र दिखाये जायेंगे जो मार्च, 2019 में बनकर तैयार हो जायेगा ।

महोदय, पटना के गर्दनीबाग में 84 करोड़ रू0 से बापू टावर तथा 866 करोड़ रू0 की लागत से पदाधिकारियों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु 1936 यूनिट आवास तथा 52 करोड़ रू0 की लागत से मंत्रियों के लिए आवासन निर्माण वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किया जायेगा ।

महोदय, 01 जुलाई, 2017 से लागू जी0एस0टी0 से पूर्व विवादित VAT से जुड़े मामलों के निष्पादन हेतु कर समाधान योजना, 2019 लाई जायेगी । 1.5 करोड़ रू0 तक टर्न-ओवर वाले कर दाताओं को अब खाता संधारण हेतु मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जायेगा । जी0एस0टी0 में मालों के मामले में निबंधन हेतु निर्धारित 20 लाख रू0 की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रू0 किया जा रहा है । इससे बिहार में 1 लाख 64 हजार छोटे कर दाताओं में लगभग आधे कर के दायरे से बाहर हो सकत हैं ।

महोदय, परिवहन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में मात्र 80,383 वाहनों का निबंधन हुआ था जो 2017-18 में बढ़कर 11 लाख 18 हजार हो गया है । महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे प्रत्येक पंचायत में एस0सी0, एस0टी0 और ई0बी0सी0 के लक्षित 42 हजार परिवारों को अनुदानित दर पर वाहन उपलब्ध कराया जायेगा ।

महोदय, अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प का मूल्य 15 से बढ़ाकर 25 रूपये किया जा रहा है । महोदय, बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित वकालतखानों के भवनों के निर्माण व रख-रखाव तथा पुस्तकालय हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जायेगी । बिहार में नोटरियों के स्वीकृत 1 हजार पदों पर नियुक्ति की जायेगी ।

महोदय, बिहार में जन धन खाते के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 4 करोड़ 12 लाख 80 हजार खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 8567 करोड़ रू0 गरीबों का जमा है । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 53 लाख 52 हजार तथा जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 15 लाख 36 हजार एवं अटल पेंशन योजना के तहत 12 लाख 29 हजार खाते खोले गये हैं । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य के 26 लाख 10 हजार लोगों को 22,388 करोड़ का ऋण बैंकों के द्वारा वितरित किया गया है।

महोदय, बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही हैं । स्वास्थ्य विभाग में लगभग 21 हजार 571 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है । उसी प्रकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 में 13,224 पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित कर 9,941 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है । आयोग द्वारा 14,310 रिक्तियों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन हो चुका है । केवल परीक्षाफल लम्बित है । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) द्वारा 2018 से महिला एवं पुरूष सिपाही हेतु 10,062 का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है । इसके अलावा 13,578 विभिन्न पदों पर भी केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) द्वारा 2019-20 में भर्त्ती की जायेगी । महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग में सिविल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पिछले 35 वर्षों से विलम्ब से आयोजित की जा रही थी । पहली बार सत्र को नियमित करते हुये 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा 2019-20 में आयोजित की जायेगी ।

महोदय, हमारे विरोधी हमपर कितना भी हमला करें, हमारा हौसला टूटने वाला नहीं है । इसलिए किसी ने कहा है अध्यक्ष महोदय,

"टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना,
बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते,
ढूंढ लेते हैं अंधेरों में हम मंजिल अपनी,
क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते ।"

अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से चुनावी वर्ष को छोड़कर राज्य में बजट उपस्थापन के बाद विनियोग विधेयक द्वारा 31 मार्च तक पूर्ण बजट पारित किये जाने की परम्परा रही है । वर्ष 2019 के चुनावी वर्ष होने के कारण बिहार विधान मंडल का सत्र अल्प अवधि का है, जिससे चालू सत्र में माँगवार विचार किया जाना सम्भव नहीं है । अत: वर्ष 2019-20 के बजट उपस्थापन के साथ लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया जायेगा । ज्ञातव्य है कि लेखानुदान सामान्यत: 4 माह के व्यय के लिए पारित किया जाता है । वर्ष 2019-20 में लेखानुदान के रूप में कुल बजट प्राक्कलन में से निर्वाचन, गृह एवं आपदा प्रबंधन मद की सम्पूर्ण राशि तथा शेष मदों के एक-तिहाई भाग की राशि व्यय करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है ।

अंत में, माननीय सदस्यगण, हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में सर्वाधिक निर्णायक, पारदर्शी एवं न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार दी है । हमने बिहार की छवि को सुधारा है, सँवारा है । हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार तेजी से विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है । हमने सतत विकास, प्रगति और जनता के बेहतर जीवन की बुनियाद रख दी है । हम बिहारवासियों के बलबूते बिहार को देश का अग्रणी राज्य बनायेंगे ।

अंत में, अध्यक्ष महोदय,

''लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती,
हौसला बुलन्द हो तो कोई दीवार नहीं होती,
जलते हुए चिराग ने आँधियों से कहा,
उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती ।''

...क्रमशः...

टर्न-15/आजाद/12.02.2019

..... क्रमशः ......

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट भाषण सदन पटल पर रखता हूँ । जय बिहार, जय भारत, वन्दे-मातरम ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अब वाद-विवाद प्रारंभ होगा । इसके लिए आज और कल यानी दिनांक 12 एवं 13 फरवरी को कुल दो दिन निर्धारित है । माननीय सदस्य श्री मेवालाल चौधरी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है तथा माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा इसके अनुमोदन का अनुरोध किया गया है ।

वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल 4 घंटे का समय उपलब्ध होगा, अगर कल हमलोग सदन का समय एक घंटा बढ़ायेंगे अन्यथा तीन घंटे हो जायेंगे । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर उनके समय का आवंटन और सरकार के उत्तर के लिए समय का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :-

राष्ट्रीय जनता दल	- 69 मिनट
जनता दल युनाईटेड	- 61 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 45 मिनट

इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 24 मिनट
सी0पी0आई0एम0एल0	- 03 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 02 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	- 01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	- 02 मिनट
निर्दलीय	- 03 मिनट
सरकार के उत्तर के लिए	- 30 मिनट

अब माननीय सदस्य श्री मेवालाल चौधरी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं । ''

अध्यक्ष महोदय, हम भी लोहिया जी का एक कोटेशन से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण शुरू करते हैं, लोहिया जी कहते थे :-

'जुबान से बोलने की नहीं, काम होगा तो खुद ब खुद असर बोलेगा।'

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है, वह पूरा परिलक्षित होता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और गठबंधन का जो भी कमीटमेंट हमारे आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा विकास के लिए था, वह हु-ब-हु जमीन स्तर पर परिलक्षित हो रहा है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह मेरी अपनी सोच है कि हमलोग बड़े खुशनसीब हैं कि हमें इतने प्रतिभाशाली और उर्जावान मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिला है कि जो एक बड़े कुशल नीतिकार हैं और उस नीति को प्रोजेक्ट के रूप में बनाकर के बखूबी ग्राऊन्ड लेवल पर जिस तरह से उतारने का प्रयास करते हैं और उससे भी ऊँचा उठकर के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर कार्यक्रम को अपने से मोनेटेरिंग करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे वित्त मंत्री और हमारे उप-मुख्यमंत्री के भाषण से भी साफ-साफ दिखता है ।

अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा गर्व होता है हमें बिहारवासी कहने का, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से ज्यादा हमारा ग्रौथ रेट है । हमारे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, जो पर-केपिटा इनकम है, हमारे अध्यक्ष महोदय वह भी बहुत सारे देशों से, बहुत सारे राज्यों से बहुत ज्यादा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के लिए सहमत है कि जो भी कार्य हमारी सरकार के द्वारा की गयी है, वह बहुत जमीन पर उतरा हुआ है और जिसके कारण यह काम परिलक्षित होता है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम अगर प्रशासनिक सुधार, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म कहते हैं, अगर आज हम उसकी बात करें तो यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लम्बी सोच थी कि हमारे जनता को भी कानूनी अधिकार दिया गया

और उसी के लिए लोक शिकायत निवारण कानून बनाया गया । अध्यक्ष महोदय, लोक शिकायत निवारण कानून से तकरीबन 4 लाख लोगों का परिवाद का फैसला हुआ । यह इतना अच्छा कानून पूरे राज्य में बनाया गया है, हर राज्य के लोग सर हमारा अनुकरण करता है । सर, इतना ही नहीं इतना अच्छा कानून बना है कि लोगों ने नेशनली और इन्टरनेशनली इसको रिकोगनाईज किया और ऐसे कानून को अभी हाल में ही 2000 का कलाम इनोवेशन ऑफ गवर्नेन्स एवार्ड, स्कॉच एवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस के लिए इनको पुरूस्कृत किया । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन्टरनेशनली कॉमन वेल्थ एसोसियेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिटिजन फोकस इनोवशन ने इन्टरनेशनली अध्यक्ष महोदय ने सार्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंगशन प्रदान किया गया है । यह हमारा इतना लोकप्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म था, जिसकी तारीफ पूरे भारतवर्ष में हुई, जिसकी तारीफ पूरे देश और विदेश में हुई ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे महामहिम के भाषण में सात निश्चय पर बहुत बल दिया गया है और आज सात निश्चय के माध्यम से सिर्फ हमारे मुखिया कल्याणकारी योजना ही नहीं बनाते हैं बल्कि एक लम्बी सोच के कारण एक बड़ा स्ट्रोन्ग बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्राऊन्ड लेवल पर बनाने का प्रयास करते हैं । जिसका साफ उद्देश्य है कि हम हर घर को शुद्ध पेयजल दें, स्वच्छता रखें तथा जो भी युवक एवं युवतियां गांव में हैं, हम उनका इतना बढ़िया कौशल विकास करें, उनमें जो क्षमता है, जो हिडेन पोटेंसियल है, हम उस पोटेंसियल को एक्सपोज करके हम उनको उस स्तर पर लायें ताकि वह अपना आयाम खुद खोज सकें । उसके लिए भी हमारी सरकार ने उसका प्रोविजन किया है ।

अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा खुशी होती है कहने में कि हम जमीन से आते हैं, गांव से आते हैं, आज तकरीबन जो वाटर एवेलेबुल है, हमको लगता है कि 2020 तक करीब-करीब 85 से 90 प्रतिशत तक हमलोग हर घर में नल दे देंगे और सबसे बड़ी बात है जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे है हमारे बिहार के पास, उस हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में कन्टमिनेशन ऑफ वाटर अभी तक कम से कम 9 डिस्ट्रिक्ट में आर्सेनिक और 11 डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराईड पाया गया है । अध्यक्ष महोदय, आर्सेनिक और फ्लोराईड को हमने देखा है, हमारे खुद कन्स्टीच्यून्सी में ऐसे 7-8 गांव हैं जो बुरी तरह से आर्सेनिक और फ्लोराईड से एफेक्टेड हैं । वहां के बच्चे को, आधे से अधिक बच्चे को बोन डिफोरमेशन हो जाती है, वे इतने हैंडीकेप्ड हो जाते हैं कि वे किसी काम के काबिल नहीं रह जाते हैं । हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे कन्स्टीच्यून्सी में गये थे तो वे खुद हमारे गांव में गये और वे इतने दयावान थे कि उन्होंने वाटर लिफ्ट करके उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की, पहले वहां वाटर ए0टी0एम0 की व्यवस्था की गई,

लेकिन वाटर ए0टी0एम0 के बाद अगर शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं हो पायी तो हमलोग उनको वाटर लिफ्ट करके पानी देने का काम किया गया ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम अगर बात करें युवा की, आज हमारे युवा की टोटल पोपुलेशन 17 प्रतिशत जो बिहार की युवा हैं आऊट ऑफ 11 करोड़ पोपुलेशन में, 1.86 करोड़ हमारे युवा हैं और युवा जब शराबबंदी के बाद एक समाज में ट्रांसफॉरमेशन हुआ, शराबबंदी के बाद एक रिफोर्म हुआ पूरे समाज में और युवा को उनके कौशल विकास के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह सोचा

...... क्रमशः .....

टर्न-16/शंभु/12.02.19

श्री मेवालाल चौधरी : क्रमशः.....कि अगर हम ग्राउंड लेवेल पर हर ब्लॉक पर कौशल विकास संस्था की स्थापना करें । इसके साथ-साथ उनको प्रशिक्षण देने के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए जिला स्तर पर हमलोग पैरा मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, पॉलीटेक्नीक कॉलेज खोल रहे हैं, जे0एन0एम0 कॉलेज खोल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं सब-डिविजन लेवेल पर आइ0टी0आइ0 और ए0एन0एम0 इन्सटीच्यूट का स्थापना किया । बेसिक आइडिया था कि जिस युवा के पास कुछ पोटेन्शियल है, जिसके पास कुछ क्षमता है उनकी क्षमता को उभार करके उन युवाओं को किसी आयाम के साथ, किसी बिजनेश के साथ जोड़ें । इतना ही नहीं हमलोग उनको बिजनेश के लिए आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत हमारी सरकार ने 500 करोड़ वेंचर कैपिटल इसमें इनवेस्ट किया और जो युवा प्रशिक्षित हो जाते हैं, जिस युवा की ट्रेनिंग हो जाती है । जिस तरह की ट्रेनिंग हो हमलोग स्मॉल और मिडियम स्केल बिजनेश के लिए 10 लाख रूपया तक उनको सपोर्ट करते हैं थ्रू बैंक, थ्रू गवर्नमेंट और वे लोग स्टार्ट देयर ऑन बिजनेश इन द स्टेट ऐंड विलेजेज । सर, आज खुशी है इस बात की बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारी ऐसी चीज है जो ग्राउंड लेवेल पर किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पर चूंकि देअर वाज सम क्वेश्चन । आज एग्रीकल्चर में जब से हमलोग कृषि रोड मैप लौंच किये हुए हैं महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का यह कृषि रोड मैप है । सर, हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कन्टीन्यूसली लास्ट 5 साल से बढ़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, आज आपने देखा कि हमारा वेजिटेबुल कल्टीवेशन-हमलोग पहले थर्ड पोजिशन में थे और हमलोग सेकेंड पोजिशन के लिए कॉपरेटिव फार्मिंग ऑफ ग्रुप फार्मिंग को प्रमोट किया है और उस ग्रुप फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हमलोगों ने 5 एकड़ वाले जमीन को या 10 एकड़ जमीन तक हर तरह की सुविधा उनको देंगे । इतना ही नहीं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिक्किम आज पहला आर्गेनिक स्टेट है और आनेवाले दिनों में हमारा राज्य दूसरा आर्गेनिक स्टेट होगा । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सिगनिफिकेंट कदम उठाया है और उनलोगों की सबसिडी 6 हजार से बढ़ाकर के 8

हजार तक कर दिया है और किसान इस बात को खुद सोच रहे हैं कि आनेवाले दिनों में जो वैल्यू, जो कॉस्ट लगेगा उससे बहुत ज्यादा बाजार में मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि जो मिल्क प्रोडक्शन है- हमलोगों ने मिल्क प्रोडक्शन में एक सिगनीफिकेंट अचीवमेंट किया है। हमारा जो सुधा एक बहुत बड़ा आर्गेनाइजेशन है या कॉम्फेड जो आर्गेनाइजेशन है- 2004-05 में साढ़े 4 लाख मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन करता था आज की तिथि में वह तकरीबन 20 लाख लीटर दूध डिस्ट्रीब्यूट करता है । उसमें तकरीबन 12 लाख लोग लगे हुए हैं, इतना मैन पावर क्रियेट करता है । अध्यक्ष महोदय, फिश प्रोडक्शन जो हम दूसरे राज्य पर डिपेन्डेंट थे आज हमलोग खुद अपना मछली पैदा करते हैं और 2017-18 में हमने 5.7 टन मछली पैदा किये हैं जबकि हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ 6.2 है । हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने टार्गेट फिक्स किया है कि हम अगले आनेवाले दिनों में तकरीबन 8 लाख मि0टन मछली पैदा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर परमिट हो तो हम दो चीज कह दें जितनी इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे टेक्नीकल एजुकेशन की बात हो, चाहे वह वेटनरी साइन्स की बात हो यह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लौंग विजनरी है कि इतने सारे युनिवर्सिटी क्रियेट करा रहे हैं। हमलोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं चाहे वह मेडिकल साइन्स का हो, चाहे वह एग्रीकल्चर साइन्स का हो, चाहे वह वेटनरी साइन्स का हो, अगर हमारे पास मैन पावर होगा तो कल आनवाले दिनों में हम हर चीज को चाहे वह एग्रीकल्चर हो, चाहे वेटनरी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कॉलेजेज हो उसके बारे में हमलोग मैन पावर डेवलप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज मौका दिया हम इसके लिए कृतज्ञ हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में जो माननीय सदस्य मेवालाल चौधरी जी बोल रहे थे, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूँ । महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से लगता है बिहार राज्य ने शून्य से लेकर शिखर तक अपनी एक लंबी यात्रा कम समय में की है और उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो लोग कभी बिहार के बारे में तरह-तरह की बात करते थे । आज पूरी दुनिया में बिहार को एक बहुत तीव्रता से विकासशील राज्य के रूप में जाना जायेगा और जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कल कहा है वह एक-एक शब्द जो राज्य सरकार ने किया है उसी का चित्रण उन्होंने किया है और मैं यह कह सकता हूं कि बिहार के 11 करोड़ जनता की विकास के लिए जो राज्य सरकार ने काम किया है वह महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक शानदार दर्पण की तरह है । आप जिस प्रकार से उसको देखना चाहते हैं आपके सामने उपलब्ध है । महोदय, किसी राज्य के लिए उसको अगर आगे बढ़ाना है तो विधि-व्यवस्था सबसे आवश्यक होता है और मैं यह कह सकता हूँ कि 2018 में 3650 कांडों में सरकार ने आगे बढ़कर सजा दिलायी है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं और मैं तो कहता हूँ कि एक सामान्य फिल्म अगर हिट होती है तो उसका पूरा श्रेय उस फिल्म के नायक पर जाता है और मैं तो यह कहूँगा कि 2005 में बिहार जहां पर खड़ा था और 2018 में बिहार आज जहां खड़ा है तो इस विकास के नायक नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार खड़ा है और खड़ा होकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का सपना देख रहा है । महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार ने कहीं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया और यही कारण है कि निगरानी द्वारा 2018 में रंगेहाथ 53 लोग पकड़े गये, आय से अधिक मामले में दो लोगों पर कार्रवाई हुई, पद के दुरूपयोग मामले में 4 लोगों पर और 59 कांड दर्ज किये गये यह सरकार की दूरदर्शिता और सरकार के कड़े निर्णय का परिणाम है । महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा हथियार बिहार की जनता के हाथ में दिया - जब बिहार की जनता अधिकारियों के यहां जाती थी, अधिकारी नहीं सुनते थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के तमाम जनता के हाथ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अनिनियम 2015 एक ऐसा हथियार दिया कि उसके मामले में 4 लाख से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई हुई है और लगता है कि यह सरकार जनता की सरकार है। यह काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। महोदय, महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार जितना कार्य हुआ है उतना कार्य शायद किसी प्रान्त में नहीं हुआ है । महोदय, महिला सशक्तिकरण के मामले में 50 परसेंट का आरक्षण देकर बिहार ने उन महिलाओं के साथ न्याय किया है जो महिला घर में बैठी रहती थी और पर्दा प्रथा के कारण उन महिलाओं की क्षमता सामने नहीं आती थी । उन महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षण पंचायतों में, नगर निकायों में देकर और राज्य के सभी नौकरियों में 35 परसेंट का जो आरक्षण राज्य सरकार ने दिया है यह नारी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण के रास्ते में मील का पत्थर हो गया । महोदय, जीविका के माध्यम से कल तक उन बस्तियों में लोग जाना नहीं चाहते थे और उन बस्तियों की गरीब महिलाओं को, उन मलिन बस्तियों के अनुसूचित जाति की ऐसी महिलाओं को अब तक 8 लाख 26 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन करके कुल 95 लाख 63 हजार परिवारों को जोड़ा गया है । यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है । महोदय, अगर घर की लड़कियां नहीं पढ़ेंगी- पहले क्या था ? लड़कियों की भ्रूण हत्या की जाती थी और लड़कियों की भ्रूण हत्या करके- लोग लड़कियों को अपने उपर एक बहुत बड़ा बोझ समझते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और उस निर्णय का असर यह हुआ कि अब लड़कियां बोझ नहीं लड़कियां सम्मान बनकर के हमारे सामने आई है । बालिका उत्थान योजना वर्ष 2018 की परीक्षा में इन्टर में उत्तीर्ण सभी कोटि के 1 लाख 66 हजार 490 अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा 10 हजार रूपये का जो अनुदान मिला है इससे हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ गयी हैं । महोदय, साइकिल योजना जो ढाई हजार रूपया था उसको बढ़ाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 हजार कर दिया है । अब हमारे बिहार की बेटी

साइकिल पर बैठती है और घंटी बजाते जब विद्यालय जाती है तो पता चलता है कि बिहार अपना उड़ान ले रहा है ।

क्रमशः

टर्न-17/ज्योति/12-02-2019

क्रमशः

श्री मिथिलेश तिवारी : अब बिहार की हर बेटी कल्पना चावला बनने का सपना देख रही है यह काम हमारे बिहार में हुआ है । महोदय, हमलोग जब जन प्रतिनिधि के रुप में गांव में जाते थे लोग एक एक लोग कहते थे पानी नहीं है पेय-जल नहीं है और इसप्रकार की बात लोग कहते थे लेकिन आज हर घर नल से जल एक ऐसी महत्वाकांक्षा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है कि अबतक 37727 वार्डो में कार्य आरम्भ हुआ जिसमें 15787 वार्डो में कार्य पूर्ण हुआ जिससे 21 लाख 55 हजार घर अच्छादित हुए । एक बड़ा काम करके हमलोगों ने दिखाया है और बिजली के मामले मैं एक मिनट लूंगा, शौचालय और बिजली के मामले में इस सरकार ने अभूतपूर्व और क्रान्तिकारी कार्य किए हैं और कल तक सड़क के किनारे बैठ कर लोग शौच करते थे, हमलोग जब गाड़ी की लाईट लेकर जाते थे तो महिलाएं सड़क पर खड़ी हो जाती थीं तो लगता था बिहार कितना पिछड़ा है लेकिन महोदय, आज घर घर में शौचालय का निर्माण करा कर स्वच्छता का जो संकल्प बिहार ने लिया है । यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम हुआ है महोदय, और मैं तो यही कहूँगा कि कल महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया और बिहार के गांव में एक नारा चल रहा है वह नारा क्या है कि न्याय के साथ विकास हमारा संकल्प है इसलिए नये बिहार का तीव्रता से विकास हेतु एन.डी.ए. ही विकल्प है, एन.डी.ए. ही विकल्प है और आज दूसरा नारा चला है, लालटेन युग का सपना देखनेवालों को सबक सिखायेंगे, लालटेन युग का सपना देखने वालों को सबक सिखायेंगे घर घर बिजली तथा एल.ई.डी. बल्ब पहुंचाने वाली सरकार को ही दुबारा सत्ता में पहुंचायेंगे, ये लोगों का संकल्प है इसलिए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूँ और एक बार आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल एवं श्री रामदेव राय, स0वि0स0 से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो नियमानुकूल हैं । श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नेता विरोधी दल - नहीं हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : प्रतिपक्ष के नेता बहुत हाई फीवर में है इसलिए उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री रामदेव राय- नहीं हैं ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, कितना गम्भीर हैं विरोधी पार्टी के लोग, बड़ा आश्चर्य होता है बजट पर अपनी बात रखनी है और सब के सब गायब हैं ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हैं बीमार पड़ते हैं तो राजगीर जाते हैं उस समय याद नहीं करते हैं ?

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : कहाँ जाते हैं कोर्ट, इ.डी. कोर्ट जाते हैं, कहां जाते हैं । क्या यही गंभीरता है, यही गंभीरता है । बजट बोलने पर कोई खड़े नहीं हैं, न ये हैं न वो हैं ।

अध्यक्ष : श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्री आलोक कुमार मेहता बोलिए न ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, कल बोलवा दीजियेगा ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव तो मूभ नहीं हुआ , कल बोलियेगा । चलिए, आलोक कुमार मेहता जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण संयुक्त सदन में पेश किया गया उसके धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में हम इस सदन में खड़े हैं । बिहार में 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तक के तमाम आंकड़ों को उस अभिभाषण के आधार पर, इस अभिभाषण को पढ़ा गया और अभिभाषण इसतरह का था जैसे लग रहा हो कि सारी झूठी और सारी असफल योजनाएं हैं सबको सजा संवार कर, इस अभिभाषण में रखा गया है । कितनी योजनाएं बिहार में चल रही हैं जिसमें सबस्डिी हो, वेलफेयर से जुड़ी हुई योजनाएं, भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ी हुई हैं । आज बिहार में जो प्राईमरी सेक्टर है, प्राईमरी सेक्टर में कृषि और कृषि जनित अन्य ऐक्टिविटी खनन, उत्खनन ये सारी ऐक्टिविटी प्राईमरी सेक्टर की उसमें बतायी गयी है और ऐसा बताया गया है जैसे बहुत भारी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और उसमें जबकि स्थिति यह है कि जो कृषि का विभिन्न क्षेत्र है जिस पर बिहार की 88.7 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है ।

(इस अवसर पर सभापति का आसन माननीय सदस्य श्री नेमतुल्लाह ने ग्रहण किया)

उस जनता की निर्भरता कृषि पर है और उस 88.7 प्रतिशत में 93.1 प्रतिशत जो रकबा है, वह रकबा एक एकड़ से नीचे का रकबा उन किसानों को है और एक एकड़ से नीचे नहीं, एवरेज लैण्ड होल्डिंग जो है वह 0.31 प्रतिशत है । 3.1 हेक्टेयर है तो एवरेज लैण्ड होल्डिंग इतनी छोटी है तो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो किसान हैं जो मजदूर है उनकी निर्भरता खाओ कमाओ वाली स्थिति तक सीमित रह गयी है उससे न कोई व्यापार हो सकता है और न उससे कोई व्यवसाय हो सकता है न वह मूल्य संवर्द्धन की तरफ सरकार का कोई ध्यान है जो कृषि आधारित उद्योगों और उत्पादनों को बढ़ावा दे नतीजा यह है कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में मात्र शून्य दसमलव ये जो अभी 18-19 का मामला है 16-17 और 15-16 जिस समय महागठबंधन की सरकार थी उस

सरकार के डाटा को भी पेश करके सरकार सिर्फ अपना पीठ थपथपा रही है जबकि 2018-19 के बाद कृषि में जो विकास का दर है मात्र 0.1 प्रतिशत है और 0.1 प्रतिशत के विकास दर पर इतना पीठ थपथपाना जिस राज्य की सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो उस राज्य की सरकार सिर्फ डेटागेमिक्स के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है चूँकि ऐसा प्रावधान और व्यवस्था रही है कि राज्यपाल को अभिभाषण देना है और सरकार ने जो दे दिया उसको पढ़ना है तो उस नाते हमारा भी विपक्ष में बैठे लोगों की यह जिम्मेवारी है कि उनकी गलतियों को जनता के सामने रखे, उनकी कमियों को जनता के सामने रखे बिहार में लौ ऐण्ड औरडर इतनी बुरी अवस्था में है आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जा रही है पहले से जो क्राईम रिपोर्ट भारत सरकार के रेकर्ड में आती थी आज स्थिति यह है कि क्राईम की संख्या घटाने के लिए एफ.आई.आर. लेना बंद किया जा चुका है और उनको जॉच के नाम पर महीनों गंभीर अपराधों में महीनों उसे टाला जाता हे कि रेकर्ड में वह नहीं आवे और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है । वेटिंग वाले का भी आंकड़ा बढ़ रहा है और जो संज्ञेय अपराध है और उसके बारे में यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो यह सारी घटनाएं भी दबा दी जाती । आज बिहार बिल्कुल असुरक्षित, बिहार के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । पहले बिहार के बाहर खिलाफ बोलने वाले लोग बिहार के ही कुछ एलीट वर्ग के लोग थे जो कहीं दूसरे राज्य में रहते थे और बिहार की बुराई करने में अपनी तारीफ समझते थे आज वही लोग उन्हीं में से कई लोग हैं जो आज यह महसूस करने के लिए जो बिहर की स्थिति है उसको यदि देखें तो उन दिनों तक बिहार के बाहर के लोग डरते थे आज बिहार के अंदर के लोग डरने लगे हैं और जो लोग यह कहते थे कि रात में 12 बजे महिलाएं निकलती हैं वह हो सकता है कि चंद इलाकों में इस तरह की बातें हो लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में आज की जो स्थिति है आप गांव देहात में जाकर देख लीजिये जो लोग 15 वर्षो को जंगल राज का नाम जिन लोगों ने दिया । क्रमश:

टर्न-18/12.02.2019/बिपिन

श्री आलोक कुमार मेहता: क्रमश: और एक झूठ को सौ बार बोलकर उसे सच में परिवर्त्तित करने की कोशिश की, वे लोग अपने गिरेवॉं में झांके कि बिहार के लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति क्या है ? एक-एक कर यदि गिनाना शुरू करूं तो शायद पूरा भाषण उसी में समाप्त हो जाए लेकिन यह बहुत गंभीर स्थिति है और बिहार की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है ।

आज बिहार में उत्पादकता और उत्पादन की बात चल रही है । 11.3 प्रतिशत् ग्रोथ रेट की बात बताई गई है लेकिन 11.3 प्रतिशत् ग्रोथ रेट में जिसका सबसे बड़ा

फैक्टर प्राइमरी सेक्टर का कृषि क्षेत्र है, उसमें ग्रोथ रेट 0.शून्य, 0.0, 0.01 प्रतिशत् है । दूसरा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जो है, दूसरा क्षेत्र जो है वह उत्खनन का है जिसका 60 प्रतिशत् कंट्रिब्यूशन प्राइमरी सेक्टर के ग्रोथ में रहा है । अब बताइए, 60 प्रतिशत् का कंट्रिब्यूशन, उस प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ रखने वाले उत्खनन के क्षेत्र के 2018-19 का जो डाटा है, उसको सामने नहीं रखा गया, अनुमानित डाटा भी नहीं रखा गया है । क्यों नहीं रखा गया ? इसलिए कि बालूबंदी हुई । बालू के दाम बढ़े, बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम बढ़े, लाखों मजदूर बेरोजगारी के कगार पर चले गए । यदि ग्रोथ रेट में मजदूरों का जो रोजगार है और जो बालू के छोटे-मोटे व्यापारी हैं, जो कंज्यूमर हैं, क्या ग्रोथ रेट में उनका हिस्सा नहीं है, यदि ग्रोथ उनके उन सभी एलीमेंट्स को मिलकर बनते हैं तो वह सबसे बड़ा लैकिंग एलीमेंट है जो कि ग्रोथ को नीचे ले जाने का प्रयास करता है । इसीलिए जानबूझ कर जो 2018-19 का आंकड़ा है, जो अनुमानित आकड़ा भी होना चाहिए था, उसे नहीं पेश किया गया । ऐसा सेकेंड्री सेक्टर का जो उत्पादन वाला क्षेत्र है, औद्योगिक उत्पादन, प्रौसेसिंग जो होता है, उस क्षेत्र में भी ऐसा ही किया गया । इस डाटा को नहीं पेश किया गया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी सेक्टर नींव है, यदि नींव हमारा मजबूत नहीं रहेगा तो हम सुपर स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे ? सेकेंड्री और टर्सियरी सेक्टर सुपर स्ट्रक्चर है । पहले जो प्राइमरी सेक्टर है उसके मजबूतीकरण की ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए था । सरकार इस मामले में बहुत ही शॉर्ट टर्म जा रही है ...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य, दो मिनट और टाइम है ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, कृषि कैबिनेट, कृषि रोड मैप तमाम चीजें बिहार में ऑपरेट हो रही है । दो कृषि मैप पूरी तरह फेल्योर हो गया बिहार में और यह तीसरा कृषि मैप लाया गया है और उस भरोसे कृषि कैबिनेट बनाया गया । अभी एम.एल.चौधरी साहब भी उस कृषि कैबिनेट के, कहीं-न-कहीं उनकी हिस्सेदारी रही थी पहले लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या प्रयोगशाला में ही कृषि के जो अन्वेषण हैं उनका प्रयोग प्रयोगशाला तक सीमित रह जाएगा ? किसानों के बीच उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन-सा प्रयास किया, इस बात को सरकार को बताना चाहिए था । आप लाख प्रयास किए लेकिन आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है, इस तरफ भी देखने की जरूरत है । बिहार में किसान भगवान भरोसे हैं । वर्षा नहीं आई, कृषि सुखानी है और वर्षा आ गई तो अपनी पीठ थपथपानी है कि बिहार में उत्पादन बढ़ गया है । वर्षा के भरोसे छोड़कर और सुखाड़ क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित न करने की जो जिद रहती है, इन तमाम वजहों से किसानों की बदहाली बिहार में बढ़ती जा रही है । किसानों को उत्पादन मूल्य का दोगुना लाभ देने की बात कही गई थी । महोदय, सरकार यह भी एक बार कैल्कुलेट कर ले कि एक क्विंटल धान के उत्पादन में कितना खर्च हो रहा है ? क्या खाद के दाम नहीं बढ़े, क्या कृषि से संबंधित जितने भी बीज और जितने भी उपादान हैं, उनके मूल्य नहीं बढ़े ?

जब उनके मूल्य बढ़े तो एक क्विंटल चावल के उत्पादन का मूल्य मात्र 11सौ कुछ रूपया कैसे हो सकता है ? यह सरकार का कैल्कुलेशन है और उसको डेढ़ गुणा बताने की कोशिश की जा रही है । 14सौ कुछ रूपया आज से तीन वर्ष पहले, चार वर्ष पहले हुआ करता था और तब उसको दोगुना यदि करें तो 28सौ रूपये क्विंटल धान के मूल्य किसानों को मिलने चाहिए थे लेकिन जितना भी दिया गया, सपोर्ट प्राइस दिया गया । जब हम उधर बैठते थे और जो लोग यहां बैठते थे तो यहां से हल्ला होता था कि धान की खरीद जो है, बहुत कम की गई, टारगेट पूरा नहीं हुआ, उस समय जब 20 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद होती थी तब । आज कितना धान की खरीद है ? आज क्यों नहीं ये बातें उठ रही हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं, हम उस सोच के लोग हैं, हम चाहते हैं कि सरकार को धान खरीदने की जरूरत नहीं पड़े ...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य, अब समाप्त करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय...महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है । महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार को किसानों का धान लेने की जरूरत ही नहीं पड़े । मार्केट का मूल्य ही उतना हो जाए और किसान को उसका मूल्य इतना मिल जाए कि वह सरकार को नहीं दे । लेकिन यह आइडियल सिचुएशन नहीं है । यह बिल्कुल ही अव्यवहारिक रूप से, सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, उसका मैनेजमेंट बुरी तरह पुअर है । सरकार सब्सिडी से लेकर तमाम चीजों पर और उससे भी ज्यादा जो बिहार के कृषि उत्पाद हैं उनके फारवर्ड लिंक हैं । बिहार का अनाज, बिहार का उत्पाद जब तक बिहार के बाहर नहीं जाएगा, तब तक बाहर का पैसा बिहार में नहीं आएगा और जब बाहर का पैसा बिहार में नहीं आएगा तो इनफ्लो ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा और जब तक इनफ्लो और इकोनॉमी नहीं होगा, तब तक कृषि क्षेत्र का संवर्द्धन नहीं हो सकता । इसलिए सरकार इस लौंग टर्म स्ट्रेटेजी पर जब तक विचार नहीं करती, बिहार के किसानों का भला नहीं होने वाला है और बिहार के किसानों को या यहां के छात्रों को, यहां के मजदूरों को, यहां की महिलाओं को इलेक्शन आने के ठीक पहले जिस तरह के पैकेज दिए जाते हैं उसे यदि दूसरा नाम सदन के बाहर दिया जाता है कि यह इलेक्शन पैकेज है तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अनैतिक है। आप ससटेनेबुल डेवलपमेंट की बात करते हैं । आप इन्क्लुसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं । कहां गया ससटेनेबुल डेवलपमेंट ? यदि धोती और साड़ी आप देते हैं, उससे बेहतर है कि धोती और साड़ी खरीदने की कूबत आप पैदा कीजिए । तब जाकर वह डेवलपमेंट ससटेनेबुल हो सकता है । ऐसे ससटेनेबुल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है । इसलिए जो अभी महिला उत्थान की बात की जाती है, महिलाओं को आरक्षण और विभिन्न तरह की बातें की जाती है, यह सारी चीजों को ढ़ँक देता है जो मुजफ्फरपुर की घटना थी । वह शर्मसार कर दिया बिहार को पूरे देश और दुनिया में । मानवाधिकार से लेकर दुनिया की जितनी भी एजेंसी है, आप कितना भी अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में स्पौंसर

करके ले आवें, मैं समझता हूं कि यह स्पौंसर्ड अवार्ड है । हमें इस बात की चिंता नहीं है कि बिहार में कृषि का और कृषि आधारित उद्योग या किसी भी तरह के उद्योग की उत्पादकता क्या है, उत्पादन क्या है, उसकी स्थिति क्या है लेकिन दिल्ली में यदि उद्योग मेला लगता है, अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग मेला और वह एक शोरूम को चमका कर आप यदि उद्योग अवार्ड ले आते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बिहार के जो आम लोग हैं, जो छोटे उद्योग के लोग हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होने वाला है । बिहार कृषि राज्य है, कृषि प्रधान राज्य नहीं, महोदय । बिहार कृषि राज्य है और कृषि राज्य में कृषि आधारित उद्योग की आवश्यकता है क्योंकि जब तक मूल्य संवर्द्धन नहीं होगा, तब तक बिहार की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, तब तक किसानों की उत्पादकता को उसके अनुरूप मूल्य नहीं मिल सकेगा । इसलिए यह सरकार पूरी तरह लगभग हर मोर्चे पर फेल है ।

महोदय, मैं एक मिनट का समय आपसे लेना चाहूंगा कि बिहार में जो छोटे जोत की जमीन है, उसकी संख्या लगभग 56 प्रतिशत् जमीन देश के 93 प्रतिशत् कम रकबा वाले किसानों के हाथ में है और वो उसपर काम कर रहे हैं, बाकी जमीनें आइडल पड़ी हुई है और उसकी उत्पादकता बिल्कुल घटती जा रही है । हम कहना चाहते हैं कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की आय को बढ़ाने और किसानों तक उसे पहुंचाने की पूरी व्यवस्था, समग्र व्यवस्था की आवश्यकता है इस राज्य को और उसके साथ-साथ यहां पर जो इन्वेस्टमेंट, जो निवेश की संभावनाएं हो सकती थी जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि निवेश की संभावनाएं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उन संभावनाओं को सारा यह लॉ-एंड-ऑर्डर का प्रॉबलंब और जो बिहार का माहौल है उन सभांवनाओं को समाप्त करता हुआ दिख रहा है । इसीलिए लॉ-एंड-ऑर्डर के क्षेत्र में सख्ती और प्रिवेंशन भी कोई चीज होती है महोदय । कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है । महोदय, जब कोई घटना घट जाएगी तो काम करके भी क्या करेगा ? किसी की जिन्दगी वापस नहीं कर सकता है.....

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए ।

टर्न- 19/कृष्ण/12.02.2019/

डा0 मु0 जावेद : सभापति महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं कृषि से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि ऑलमोस्ट 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं । महोदय, हमारी जो आज की सरकार है, कृषि रोड मैप के बारे में वह बता रही थी तो मैं बताना चाहता हूं कि जो बदहाली किसानों की बिहार में है, शायद ही किसी स्टेट में होगा । न तो समय पर बीज मिलता है, न खाद मिलता है और न समय पर उनका अनाज खरीदा जाता है । सरकार कहती है कि धान प्रति क्वींटल 1750/-रूपया लेंगे । लेकिन आप बिहार के

किसी कोने में चले जाईए, 1300/- या 1350/- रूपये प्रति क्वींटल धान बिकता हर हाट में दिखेगा । वह इसलिए कि यह सरकार चाहती है कि बिचौलियों की तरक्की हो, किसानों की नहीं ।

सर, कई पैक्स ऐसे हैं, जो अभी धान खरीदना ही शुरू नहीं किया है और न ही उसपर सरकार की ओर से दबाव है । मैं चाहता हूं कि उसी तरह जिस तरह से एम0एस0पी0, धान और मकई में है, हमारे तरफ चाय और पटुआ की खेती होती है, उसमें भी एम0एस0पी0 लागू होना चाहिए ताकि किसानों का सम्मान बचा रहे । कृषि रोड मैप के तहत मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं । आज हमने समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स में देखा कि बिहार में मछली के उत्पादन के लिये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पानी है और उत्पादन 59 करोड़ किलोग्राम है । अगर हम इसको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करें तो 15 ग्राम मछली हमको मिलता है और मीट का उपज उससे भी कम है। वह लगभग 8 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति साल है, जो बहुत ही कम है ।

महोदय, मैं एजुकेशन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वह भवन की बात हो या बेंचेज की बात हो या स्टडी मेटेरियल्स की बात हो या शिक्षकों की क्वालिटी या उनकी संख्या की बात हो, सब में गिरावट है । महोदय, मेरा इसमें सुझाव होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति के समय अच्छी तरह से उनका चयन करना चाहिए । चूंकि इस पर हमारे बच्चों का और हमारे राज्य का भविष्य इस पर निर्भर है ।

महोदय, हमारे यहां किशनगंज में जो जिला मुख्यालय है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पिछले सत्र में हमने 10 दफे सदन में इस बात को उठाया, वहां मात्र तीन हाई स्कूल्स है, आप बताईये जहां डेढ लाख की आबादी हो, वहां पर तीन हाई स्कूल हैं । तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार का क्या जेहन है शिक्षा के प्रति । महोदय, यहां पर तीन सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, मदरसा की हालत बदहाल है, मदरसा के शिक्षकों को उसके अनुकूल जो पेमेंट मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है जिसके कारण उसका प्रोडक्टीविटी कम है । मेरी आपसे गुजारिश होगी कि लगभग 2500 मदरसा है, वैसे 800 मदरसा को रीकॉगनाईज किया गया है, बाकी मदरसों को भी रीकॉगनाईज करना चाहिए । महोदय, हमारी यू0पी0ए0 सरकार ने किशनगंज और सीमांचल एरिया को पिछड़ा देखते हुये उन्होंने निर्णय लिया कि ए0एम0यू0 की वहां शाखा खुलेगा । लेकिन कई सालों तक इस सरकार ने वहां जमीन उपलब्ध नहीं कराई । महोदय, हमलोगों को इसके लिये सड़क पर उतरना पड़ा । लाखों की तादात में शाांतिपूर्वक हमलोग वहां उपस्थित हुये, जिसके कारण हमें जमीन मिली । लेकिन जमीन विलंब से मिली । जैसे ही जमीन मिली हमने प्रोसेस शुरू किया और 137 करोड़ लगभग एलॉट करने के बाद हमारी यू0पी0ए0 की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी

मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ए0एम0यू0 का फाउंडेशन ले हुआ । लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इन पिछले पांच सालों में जो हमने एलौट किया था उसका 10 करोड़ रूपया भी उस जमीन पर नहीं लगाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार सबकी तरक्की पसंद नहीं करती है और जो इलाका पिछड़ा है उसको और अधिक पिछड़ा बनाना चाहती है । सर, 2013 में टी0ई0टी0 एग्जाम हुआ था और वेकेंसी 2700 निकली थी, जिसमें बड़ी मुश्किल के बाद, सरकार में पार्टिसीपेशन था, 1200 लोगों की नियुक्ति हुई । लेकिन आज भी 15000 नियुक्तियां नहीं हुई । क्यों नहीं हुई ? मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि वह 15000 को भी लेना चाहिए जो टी0ई0टी0 ग्रेस नंबर देकर पास हुये हैं और राजस्थान के मोडल से पास किया जा सकता है ।

सर, लोन के बारे में बताया जा रहा है कि 909 करोड़ रूपया दिया गया है । 909 करोड़ रूपया 30-32 हजार रूपया स्टूडेंट्स को दिया गया है । क्या यह नाकाफी है । जिस राज्य की आबादी करीब 11 करोड़ है, उमसें यह नाकाफी है ।

सर लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में जितना कम बताया जाय, उतना बेहतर है। दिन-दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है, दिन-दहाड़े पेरेंट्स के सामने बच्चियों का वायलेट किया जाता है, उनकी इज्जत पर हाथ डाली जाती है । यह बिहार में शर्मनाक स्थिति है। इसको सुधारने की जरूरत है ।

सर, पुल के बारे में मैं कहना चाहता हूं । सरकार ने बताया कि 8 मेगा पुल बने हैं, 2,124 पुल बने हैं । लेकिन हमारा इलाका, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, वहां पर नदियों की भरमार है, वहां पर पुलों की कमी है, खास करके भोटाथाना और खरखरी में महानन्दा में पुल की सख्त जरूरत है। उसी तरह लोचापुल टेढ़ाघाट में भी पुल की सख्त जरूरत है ।

सर, अभी सरकार की ओर से बताया गया कि ओ0डी0एफ0 स्कीम के तहत लगभग 1 करोड़ टायलेट्स बने हैं । इसमें बिहार में सबसे बड़ा गरीबों के साथ घोटाला हुआ है । सरकार ने गरीबों से टायलेट बनवाया, लोगों ने लोन लेकर टायलेट बनवाया और उसके सूद का रकम दुगना हो गया । जब वे सरकार से पैसा लेने जाते हैं तो इनके जो ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं, किसी को पैसा नहीं देते हैं जब तक कि उनको हजार से पन्द्रह सौ मिल नहीं जाता है । गरीबों पर यह बहुत बड़ा अत्याचार है । हम इसको ऑब्जेक्ट करते हैं और सुशासन सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको रोकिये और जितने शौचालय बनाये गये है, जल्द से जल्द उनको पैसा दिलावाने का काम करें ।

सर, पर्यावरण के बारे में बताना चाहता हूं । किशनगंज चूंकि नेपाल और बंगाल के बोर्डर पर है, वहां पर कई इंट भट्ठे हैं । सरकारी रेट 6 रूपये के आस-पास है, लेकिन अगर आप इंट खरीदना चाहे तो आपको 11 या साढ़े 11 रूपये इंट लोकल गरीब लोगों को मिलता है, जो सरासर नाइंसाफी है । उससे

जमीन हमारा खराब होता है, पानी हमारा खराब होता है, वायु हमारा खराब होता है लेकिन हमें इंट दुगने दाम पर दिया जा रहा है और यह सब इंट बंगाल और नेपाल जा रहा है, कोई रोकनेवाला नहीं है । वहां के सरकारी ऑफिसर्स हैं, वे लोग इसको कमाई का एक जरिया बना लिये हैं ।

सर, किशनगंज शहर में एक नदी बहती है, जिसके बारे में इस सदन में पिछले बीस सालों से अलग-अलग वक्त में हमने उठाया है लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है । नदी के दोनों तरफ जो तट हैं, उसपर भूमाफियाओं ने जिला और प्रखंड स्तर के ऑफिसर्स से मिलकर करोड़ों अरबों रूपये की जमीन का घोटाला करके बेच दिया है ।

सभापित (श्री मो0 नेमातुल्लाह) : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

डा0 मु0 जावेद : सर, मैं यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं । यह इसलिए कि हर शहर में आज के दिन में आबादी बढ़ रही है । लेकिन किशनगंज ऐसा शहर है । यह नदी जो नाला बन गया है, यह छः महीने महकती रहती है, जिसके कारण किशनगंजवासी बीमार पड़ रहे हैं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इसकी जल्द से जल्द नपाई करा करके इसके तटों पर अवैध रूप से जो कब्जा कर लिया गया है, इसको हटाया जाय और इस नदी को फिर से चालू कराया जाय । जो भूमाफिया है, उन्होंने अवैध कब्जा करके नदी को जाम कर दिया है, जिसके कारण नदी का पानी आगे बढ़ना रूक गया है ।

क्रमशः

टर्न-20/अंजनी/दि0 12.02.2019

डॉ0 मो0 जावेद......क्रमशः : सर, हमारा इलाका सबसे पिछड़ा है । चाहे पढ़ाई का मसला हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, आप इसका एनालीसिस कर लें, सब में पिछड़ा है । इसी के तहत जितने भी वहां के लोग हैं, किसी-न-किसी तरह उनको आरक्षण मिला हुआ है । एक समाज जो छूटा हुआ है, वह सुरजापूरी है, जिसको वर्ष 2004 में हमलोगों ने बड़ी मुश्किल से एनेक्सचर-2 में लाने की कोशिश की और कामयाबी मिली, इसको एनेक्सचर-1 में लाने की जरूरत है । माननीय मुख्यमंत्री जी जब एग्रीकल्चरल कॉलेज का शिलान्यास करने गये थे, हमलोगों ने फरियाद रखी थी तो उन्होंने कहा था कि इसको लागू कराने की कोशिश करेंगे । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि अतिशीघ्र इसको लागू कराया जाय ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त करिए ।

डॉ0 मो0 जावेद : महोदय, हेल्थ के बारे में यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टर और नर्सिंग की सख्त कमी है और दवाईयां भी नहीं मिल रही है और इसके वजह से सब लोग प्राइवेट

इन्स्टीच्यूशन में जाते हैं, नर्सिंग हॉम में जाते हैं जो गरीबों के लिए मुश्किल पड़ जाता है। मेरा आग्रह होगा कि इसपर भी आपको ध्यान देना है । आखिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सदन में लाना चाहता हूँ कि वह टूरिज्मि के बारे में । सर, हमारे यहां हिन्दुस्तान में लगभग एक करोड़ टूरिस्ट आये और जिनके माध्यम से लगभग दो लाख करोड़ की आमदनी हुई भारत सरकार में और उस एक करोड़ में लगभग 11 परसेंट बिहार में आये, जैसा कि इनका आंकड़ा बता रहा है । मैं यह कहना चाहता हूँ, सौभाग्य है कि बिहार में बुद्धिज्मि का सेंटर है, जैनेज्मि का सेंटर है, सिखिज्मि का सेंटर है, जिसकी आबादी.....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सूफी, संतों का भी है ।

डॉ0 मो0 जावेद : सूफी, संतों का भी है, जिनकी आबादी लगभग 60 से 70 करोड़ है, वहीं पर मुसलमानों की आबादी इस दुनिया में 160 करोड़ है । सउदी अरबिया, जहां मक्का है, वहां उनकी आमदनी सिर्फ टूरिज्मि से चार से पांच लाख करोड़ रूपये होती है । अगर उसी को हम एक बेस मान लें और इन स्थलों को हम बेहतर बनायें, प्रोपर इनफ्रास्ट्रक्चर दें, एसिस्टेंस दें तो हमारी जितनी भी साल भर की जो बजट है, जो एलोकेशन है, उससे ज्यादे की आमदनी इन टूरिज्मि से होगा तो इसपर भी सरकार गौर करे । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, राज्यपाल द्वारा लाये गये अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में आदरणीय सदस्य माननीय मेवालाल चौधरी जी ने जो अपनी बातें प्रस्तुत की है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार, सम्मानीय सुशील कुमार मोदी और एन0डी0ए0 गठबंधन के सुशासन की सरकार में बिहार प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जायेगा । चाहे जिस क्षेत्र को आप देखें, बिहार प्रगति के रूप में एक मानक स्थापित कर रहा है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में लें, कभी सरकारी अस्पतालों में गाय, सांढ और कुत्ते बैठते थे, आज हजारों की संख्या में वहां मरीज जाते हैं, उनका इलाज हो रहा है, लोगों को दवाईयां मिल रही है । माननीय सदस्य जो टोका-टोकी कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चालू किया था, जिसमें 30 हजार रूपये का बीमा गरीबों के लिए शुरू किया था । साल में 30 हजार रूपये मिलेंगे आपको इलाज कराने के लिए, मात्र एक बार वह योजना इस बिहार में लागू हुआ और दूसरी बार जिस हॉस्पीटल में इलाज कराया 30 हजार रूपये के अंतर्गत, उनको वह पैसे नहीं मिले लेकिन आज की सरकार ने पांच लाख रूपया आयुष्मान भारत के अंतर्गत देकर वैसे गरीब मजदूरों का इलाज करने के लिए और सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, उसके पूरे परिवार का इलाज हिन्दुस्तान के चाहे जिस अस्पताल में कराना चाहे, आज के

दिन में इलाज हो रहा है । इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा । महोदय, आप दूसरे क्षेत्र को भी ले लीजिए, जिस माननीय के राज में 55 सालों तक डिबरी जला, जिस माननीय के राज में, जिस सरकार में 55 साल के बाद लालटेन जुगाया और आज उस माननीय सदस्य के घर में बिजली जल रही है । उस माननीय के घर में भी उजाला हो रहा है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा । वैसे आज डिबरी के भाई और लालटेन के भाई आज के दिन में अपने घर में उजाला की रोशनी में, बिजली की रोशनी में वे बिजली का उपयोग कर रहे हैं, इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए । महोदय, शराबबंदी की बात में टोका-टोकी होती है कि शराबबंदी हुआ लेकिन पूर्णरूप से लागू नहीं हुआ । आप ईमानदारी से, अपने कलेजे पर हाथ रखकर कोई माननीय कह दे, जब बिहार में शराब खुले रूप में बिकती थी और माननीय लोग गांव में जाते थे, वैसे गरीब बस्तियों में बैठते थे और जब दो आदमी शराब पीकर आकर उनके सामने नौटंकी करता था, पूछता था कि नेता जी, हमरा गांव के रोड का क्या हुआ, नेता जी, हमारे विकास का क्या हुआ, जब मूंछ ऐंठता था, शरीर पर ताव चढ़ाता था तो नेता जी तुरंत उससे खिसक जाते थे कि इस शराबी से कौन उझरायेगा । आज की सुशासन की सरकार ने शराब बंद करके वैसे माहौल में परिवर्तन लाने का जो काम किया, आज आप कहीं भी जाइए, चौक-चौराहे या गली मुहल्ले में बैठिए, घंटो बैठिए और बोलिए । पहले आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था । अगर कोई गलती से शराब चोरी से पी ही लिया है और जैसे उसको पता चलता है कि पुलिस आ जायेगी, प्रशासन आ जायेगा या तो वह वहां से खिसक जाता है, नहीं तो अपने को साईड कर लेता है, नहीं तो वह डर जाता है।

आज बात कृषि की हो रही है, कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कृषि में तो किसानों की हालत खराब है । मैं मानता हूँ कि कुछ मामले में किसानों की हालत खराब होगी । (व्यवधान) मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात गौर से, मैं मानता हूँ कि आज के दिन में कई किसान अपने फसलों को नष्ट कर रहे हैं, क्यों ? कृषि का उत्पादन अगर अधिक नहीं बढा होता तो फसल नष्ट करने का, वह अनाज नष्ट करने का अवसर कैसे आता ? आज के दिन में सिर्फ कृषि क्षेत्र में कृषि का बढ़ावा ही नहीं हुआ है, जो आंधप्रदेश की मछलियां, माननीय सदस्य के गांव में, माननीय सदस्य के घर में खरीदकर आता था, खाते थे, आज बिहार में मछली का उत्पादन बढ़ा है । आज बिहार में जो फूल बंगाल से आते थे गाड़ियों में लदकर, आज बिहार में भी फूलों की खेती हो रही है । जिस माननीय सदस्य को विश्वास नहीं हो तो चलिए, आप चम्पारण में देखिए, जो कलकत्ते से बासी फूल आता था, वह आज बंद हो गया है । महोदय, मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से दूध का उत्पादन बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में पहले इसमें सुधा काम करती थी, आप चलिए, चम्पारण के इलाके में मदर डेयरी भी प्रतिदिन एक

लाख लीटर दूध का प्रोसेसिंग कर रही है और 70 हजार से अधिक किसान, आज का जो वर्त्तमान का रेकर्ड है, उसमें 70 हजार से अधिक किसान के घर में महीने के 3 तारीख, 13 तारीख और 23 तारीख को उसके दूध के दाम जा रहे हैं । न तो एक ग्राम कम जोखना है और न एक पैसे उसमें कम आने हैं और किसान को बोनस के रूप में भी, उसकी आमदनी और उसकी भरपाई उसको साल में एक बार होती है । किसानी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है । महोदय, जिन लोगों ने 55 साल, 65 साल तक गरीब के आंखों से आंसू गिराया, आज उसके घर में गैस पर खाना बन रहा है। ऐसे लोगों को खराब लग रहा है जो गरीब को लकड़ी के चूल्हा पर मजबूर करते थे कि आप चूल्हा झोंकिए अपनी आंखों को खराब कर लीजिए । आप दमा पकड़वा लीजिए, टी0बी0 पकड़वा लीजिए, इनको कभी याद नहीं आया कि उस गरीब के घर में भी गैस जलना चाहिए । आज उन गरीबों के घर में एन0डी0ए0 की सरकार गैस जलवा रही है और गरीब का खाना समय पर बन रहा है । महोदय, कभी याद नहीं आया कि गांव के गरीब मां-बेटियों की इज्जत जो सड़क के किनारे बैठकर दिखला रहे थे, आज एन0डी0ए0 की सरकार ने 12-12 हजार रूपया वैसे सभी गरीब परिवारों को देकर सबके घर में इज्जत घर बनवाने का काम किया है । मैं मानता हूँ कि कुछ मामले में हमारी कमियां हो सकती है, इलेक्शन का समय है, हमारे पदाधिकारी, अधिकारी कई कामों में फंसे हुए हैं, समय पर उनका पैसा नहीं जा रहा है ।

....क्रमशः....

टर्न-21/राजेश/12.2.19

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, क्रमशः: लेकिन आज वैसे इज्जत उघाड़कर बिहार की सड़कों पर दिखाने के लिए एन0डी0ए0 की सरकार मजबूर नहीं कर रही है, इनलोगों ने 65 सालों तक वैसे हमारे परिवार की बेटी बहू को नंगा करके दिखाया, महोदय, जिन लोगों ने 70 सालों तक लोगों को गैस, राशन, किरासन के दूकानों पर लाइन लगाकर रखा, कभी उनको लाभ नहीं लेने दिया लेकिन आज एन0डी0ए0 की सरकार में पैसे खाते में जा रहे हैं और उसका लाभ उसे मिल रहा है । महोदय, वह समय भी याद है, 2005 से पहले का वह समय था जब ब्लॉक में इंदिरा आवास का बोली लगता था, महोदय उस समय को भी याद करना चाहिए, जब 2005 से पहले का समय था, रुपया कैश बटाता था, हमलोग उस समय ब्लॉक के प्रमुख थे, ब्लॉक में बैठते थे, रुपया का गड्डी आता था

और वही पर चार दलाल बैठकर रुपये का बंदरबॉट करता था, ये हमारे मित्रगण बता दें कि 2005 के पहले जितने भी इंदिरा आवास दिया गया गरीब परिवारों को, चाहे वह अनुसूचित जाति बस्ती में दिये हो या पिछड़ी बस्ती में दिये हो, कितने लोगों का घर ये लोग बनवा पाये लेकिन आज एन0डी0ए0 की सरकार डेढ़ लाख रुपया उनके खाते में दे रही है, आज सरकार दे रही है, तो इनलोगों का कलेजा फट रहा है, इनके कलेजे पर सॉप रेंग रहा है कि आज यह क्या हो रहा है बिहार में ....(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): माननीय सदस्यगण, बीच-बीच में टोका-टोकी ना करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, आज सरकार सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रही है । सभापति महोदय, ये लोग पूरे बिहार में एक भी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाये थे और महोदय जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो उसने बिहार में दो-दो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, एक गया में और दूसरा मोतिहारी जिले में खोल कर हमारे राज्य के बच्चों को पढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है, तो इनके कलेजे पर जूं रेंग रहा है कि आज बिहार के छात्र क्यों पढ़ लिख रहे हैं............ (व्यवधान)

श्री अवधेश नारायण सिंह: सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): क्या आपका प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री अवधेश नारायण सिंह: सभापति महोदय, गया सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी कृषि मंत्री बैठे हैं और मोतिहारी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ये दोनों यूनिवर्सिटी को यू0पी0ए0 गवर्नमेंट ने खोला है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय सदस्य बोल रहे हैं सरकार का जवाब अगर हो तो प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर उठिये लेकिन ये प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है । जब कोई माननीय सदस्य कोई बात कह रहे हैं, तो इनको सुनना चाहिए, प्वायंट ऑफ ऑर्डर तो तब होगा जब सरकार का उत्तर होगा ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य यह कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। माननीय सदस्य सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी, आप बोलिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, तो ये माननीय सदस्यगण कलेजा पीट रहे हैं, बिहार के नौजवान जब एन0डी0ए0 के द्वारा खोले गये सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये कलेजा पीट रहे हैं, आज एन0डी0ए0 की सरकार ने तय किया है कि 2022 तक हम बिहार को भी और भारत को भी हॉटलेस इंडिया बनायेंगे, हॉटलेस बिहार बनायेंगे, झोपड़ीरहित बिहार बनायेंगे, तो इनके कलेजे पर सॉप रेंग रहा है, जब आप 25 हजार रुपये देते थे और उसमें भी 20 हजार रुपये का बंदरबाट कर लेते थे लेकिन आज गरीबों के खातों में डेढ़ लाख रुपया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होना है, तो इनके कलेजे पर जूं रेंग रहा है, आज ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि बिहार की सरकार ने सड़कों के मेनटेनेंस के लिए मेनटेनेंस पॉलिसी बनाया है, सड़कों का मेनटेनेंस हो, चाहे सड़कें आर0डब्लू0डी0 की बनी हो, दूसरे किसी भी योजना से

चाहे वह विधायक निधि से बनी हो, चाहे एम0पी0 योजना से बनी हो, चाहे गॉव पंचायत से बनी हो लेकिन जो उसका मेनटेनेंस पॉलिसी बनाया है कि सभी सड़कें अच्छी हो, बेहतर हो, जिसपर आपकी गाड़ियां दौड़ेगी, आज आप कह सकते हैं कि बिहार की सरकार ने 7 निश्चय में गली, नली का काम शुरु किया है, जब माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में एम0जी0एस0वाई0 की अनुशंसा करते हैं, तो इनके यहॉ के मुखिया जी, वार्ड सदस्य आकर कहते हैं कि विधायक जी गलिया वाला सड़क को छोड़ देवल जाऊ, गलिया वाला सड़क ना छोड़ब तो हमनी सब कौन चीज बनाऊ, तो आज बिहार में हमारी सरकार सड़कों की जाल बिछा रही है, कई एन0एच0 बन गये बिहार में, सी0आर0एफ0 से कई रोड बन रहा है महोदय और इन सब बातों को देख कर इन माननीयों के कलेजों पर सॉप रेंग रहा है, क्योंकि ये लोग तो अधिक दिनों तक डिबरी युग में रखे बिहार को, इनलोगों ने अधिक दिनों तक लालटेन युग में रखा बिहार को, और आज जब बिहार उजाला में आया है, जब बिहार मुद्रा योजना का लाभ ले रहा है और वैसे ठेला, खोईचा चलाने वाले लोग भी चौक चौराहों पर छोटी-छोटी दूकान करने वाले लोग भी, चाय बिस्कुट बेचने वाले को भी मुद्रा योजना के अन्तर्गत पॉच हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन मिल रहा है, तो इनके कलेजे पर सॉप रेंग रहा है । एक समय था बिहार में महोदय, जब बेटियॉ होती थी, तो उसको अभिशाप माना जाता था लेकिन आज एन0डी0ए0 की सरकार कह रही है कि बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओ और उसके अन्तर्गत सुकन्या समृद्धि योजना चला कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी को सुरक्षित करने का काम, बेटी को संरक्षित करने का काम और उसको पढ़ाने का काम शुरु किया है ताकि शादी ब्याह के दिन भी उस बेटी को कोई प्रॉबलम न हो, उसके गार्जियन को कोई प्रॉबलम न हो, तो आज इनलोगों को परेशानी बढ़ रही है कि हमारा क्या होगा ? सभापति महोदय, इतना दिनों तक जो करके आये हैं, उसका ये लोग फल भोग रहे हैं और आगे भी इनलोगों को भोगना पड़ेगा । महोदय, इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में भी आज मैं इनलोगों को न्योता दे रहा हूँ, वैसे माननीय सदस्यों को जिनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप चलिये चंपारण, आप मोतिहारी के इलाके में चलिये आपको विकास दिखाई पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर कॉलेज आपको दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, जिससे किसानों का आमदनी बढ़े, आज उनको फ्री में मधुमक्खी का बक्शा दिया जा रहा है, तो आज इनको चिंता हो रही है कि अल्पसंख्यक आज हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, आज उनको सरकार के द्वारा मुर्गीपालन करने का, बकरीपालन करने का एवं सभी कामों में उसको स्कील्ड करके मुद्रा योजना से एवं अन्य योजना से उसको लाभ देने का काम कर रही है ताकि वह अच्छा काम कर सके । आज गन्ना का उत्पादन बढ़ा है, जो कृषि क्षेत्र में आता है, आज केला का बागवाणी लग रहे हैं बिहार में, जिससे इसका उत्पादन बढ़ा है, तो इनलोगों का

कलेजा फट रहा है कि अब क्या होगा, तो जो ये लोग किये हैं, वह तो इन्हें भोगना ही पड़ेगा, जो कर्म किये हैं, उसका फल तो निश्चित रुप से मिलना ही मिलना है और आगे भी मिलता रहेगा, थोथी दलील देने से, झूठी बात बोलने से, असत्य बात करने से, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है,

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

बिहार आज लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता रहेगा और आगे ही बढ़ेगा, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रति आदर समर्पित करते हुए कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, माननीय सभी सदस्यों, बहनों, भाईयों के प्रति सादर समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ । जय बिहार, जय एन0डी0ए0 ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: फराज जी और समीर जी, अगर आप दोनों की इजाजत हो, तो आसन कुछ बोले ।

माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर जो वाद-विवाद चल रहा है, वह कल दिनांक 13 फरवरी, 2019 को भी जारी रहेगा ।

आज दिनांक 12 फरवरी, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-10 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 13 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(बैठक 4.00 बजे अप0 में स्थगित हुई)